राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 31 जनवरी 2026 वर्ष-9,अंक-08 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बारामती में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन

एजेंसी

महाराष्ट्र। पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियों का विसर्जन शुक्रवार को बारामती में संगम तट पर किया गया। इस मौके पर उनके बेटे जय पवार और पार्थ पवार के अलावा एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी मौजूद रहे। इससे पहले सुबह दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों और एनसीपी नेताओं ने विद्या प्रतिष्ठान मैदान से उनकी अस्थियां ग्रहण कीं। इसके बाद विधि-विधान के साथ संगम तट पर अस्थि विसर्जन संपन्न हुआ।गौरतलब है कि अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में हुए एक विमान हादसे में निधन हो गया था। इस दुर्घटना में उनके साथ चार अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। हादसे के अगले दिन, 29 जनवरी को, उनका अंतिम संस्कार बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की।अंतिम संस्कार की रस्में गुरुवार को दोपहर में शुरू हुईं। अजित पवार के पुत्र पार्थ और जय ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी।

राजस्थान में साध्वी की संदिग्ध हालत में मौत

एजेंसी

राजस्थान। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा (23) की विवादित मौत के बाद आज उन्हें समाधि दी गई। बाईसा को बुधवार को जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ का दावा है कि उन्हें केवल मामूली जुकाम था। जोधपुर के ही आश्रम में उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल में मौत के बाद उनका एक कथित सुसाइड नोट सामने आया था। इसके बाद साध्वी से जुड़ा पुराना ब्लैकमेलिंग केस फिर चर्चा में आ गया है। वहीं, कई भक्तों ने उनके पिता की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। 13 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वे एक व्यक्ति के गले मिलते नजर आ रही थीं। इसे अश्लील बताकर प्रचारित किया गया था।

महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि, मोदी ने श्रद्धांजलि दी

राहुल गांधी बोले- राष्ट्रपिता का मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। PM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। राहुल गांधी ने लिखा कि राष्ट्रपिता ने हमें मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। राहुल गांधी ने पर लिखा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच हैं। वह सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की। मगर राष्ट्रपिता ने हमे

आजादी के साथ यह मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस। यह सोच मिट नहीं सकती, क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। जयराम रमेश का BJP सांसद पर तंज कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने महात्मा गांधी की बिना नाम लिए पूर्व जज और BJP सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना की। जयराम रमेश ने लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या से दो दिन पहले जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था। इसके कुछ महीनों बाद, 18 जुलाई 1948 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था। इन दोनों पत्रों में स्वयं को राष्ट्रवाद का स्वघोषित संरक्षक बताने वालों पर बेहद गंभीर आरोप हैं। यह सोचकर हैरानी होती है कि उसी विचारधारा से जुड़े एक लोकसभा सांसद, जिन्हें प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने यह कहा कि वह गांधी और गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकते। उनकी यह मानसिकता बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में सरदार पटेल कॉरस्पोंडेंस (19451950) किताब के पन्नों के साथ 30 जनवरी 1948 की रात को ऑल इंडिया रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू के भाषण का लिंक भी साझा किया। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हर साल 30 जनवरी को मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देशभर में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

शीर्ष नेतृत्व तक ले जाउंगा अपनी बात

कांग्रेस बैठक में शामिल नहीं होने पर ऐसा क्यों बोले थरूर

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर हुई पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उन्होंने पहले से तय यात्रा का हवाला दिया है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ पार्टी नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पी चिदंबरम, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और मनीष तिवारी जैसे नेता शामिल थे।कांग्रेस में पिछले चार

दिनों में यह दूसरी उच्च स्तरीय नेताओं की बैठक थी, जिसमें थरूर शामिल नहीं हुए। पिछले हफ्ते वह आने वाले केरल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक में भी मौजूद नहीं थे। बैठक में शामिल न होने के लेकर शशि थरूर की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मुझे जो भी मुद्दे उठाने हैं, मैं उन्हें सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे वह मौका मिलेगा, खासकर जब संसद के सत्र के दौरान सब साथ होंगे। आज की बैठक में शामिल न होने की बात करें तो, निमंत्रण कल या परसों ही आया था, तब तक मेरे ट्रैवल प्लान पहले ही तय हो चुके थे।

कैफे हत्या मामले का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

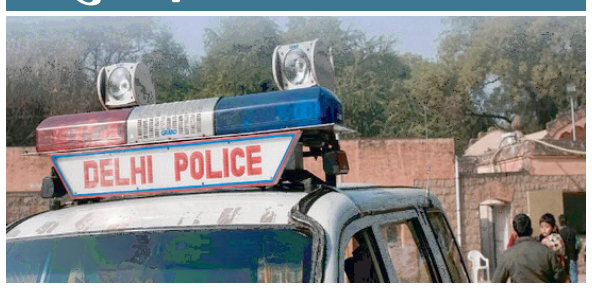

एजेंसी

नई दिल्ली। थाना वेलकम क्षेत्र में एक कैफे में हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वांटेड आरोपी मुइन कुरैशी को तिमारपुर इलाके में हुई संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी तड़के स्पेशल सेल की टीम ने की।मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। लंबे समय से पुलिस को मुइन कुरैशी की तलाश थी। फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।

माघी पूर्णिमा पर स्नान के लिए शंकराचार्य को मनाने में जुटे

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रखी ये शर्तें

एजेंसी

प्रयागराज। ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज माघी पूर्णिमा पर संगम में डुबकी लगा सकते हैं। लखनऊ के कुछ उच्चाधिकारियों ने शंकराचार्य से संपर्क कर उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारी शंकराचार्य से माघी पूर्णिमा पर संगम में स्नान के लिए आग्रह कर रहे हैं। शंकराचार्य ने स्नान करने के लिए कई शर्तें भी अधिकारियों के सामने रख दी हैं। जिसमें मौनी अमावस्या को अभद्रता करने वाले अधिकारी लिखित में माफी मांगें, संन्यासियों, बटुकों, ब्राह्मणों, साधु-संतों और वृद्धों की पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के साथ एफआईआर हो, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और चारों शंकराचार्यों के स्नान के लिए प्रोटोकॉल बने समेत ये चार मांग की हैं। यह सभी चार मांगें मानने पर ही शंकराचार्य ने स्नान की बात कही है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने की है।मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने जा रहे ज्योतिष्ठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को

पुलिस प्रशास ने संगम जाने से रोक दिया। उनके रथ और जुलूस को रास्ते में रोकने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। रथ रोकने पर शंकराचार्य के समर्थक साधु-संतों और पुलिस में तीखी नोकझोंक हो गई। अधिकारियों ने कहा कि पैदल जाकर स्नान करें, जिस पर विवाद और बढ़ गया। घटना के बाद देखते ही देखते पूरा संगम क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। गृह सचिव मोहित गुप्ता, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर शंकराचार्य ने संन्यासियों, ब्राह्मण बटुकों और साधु संतों के साथ मारपीट करने और उनकी चोटी पकड़कर घसीटने और अपमानित करने का आरोप लगाया। घटना से मर्माहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज माघ मेले में त्रिवेणी मार्ग पर स्थित अपने बद्रिकाश्रम हिमालय शिविर के सामने सड़क के किनारे धरने पर रहे। यह धरना मौनी अमावस्या 18 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक चला। वह अधिकारियों से माफी मांगने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। 28 जनवरी को शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर वाराणसी के लिए रवाना हो गए।मौनी अमावस्या की घटना के बाद धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके पूछा था कि साबित करें की आप ज्योतिष्ठ मठ के शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है तो आप क्यों नाम के आगे शंकराचार्य लिख रहे हैं।

केंद्रीय बजट से शिक्षा और रोजगार क्षेत्र को क्या-क्या उम्मीदें

एजेंसी

नई दिल्ली।

देश की संसद में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12वां आम बजट होगा। केंद्र सरकार के इस आगामी बजट से शिक्षा और रोजगार सेक्टर में कई नई पहलों की उम्मीद की जा रही है।ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में शिक्षा पर होने वाले खर्च में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि शिक्षा और रोजगार दोनों ही क्षेत्रों को बजट में खास प्राथमिकता मिल सकती है। आइए जानते हैं कि इस साल के बजट से शिक्षा और रोजगार क्षेत्र को लेकर क्या-क्या उम्मीदें हैं।आज के डिजिटल युग में शिक्षा को तकनीक से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। लेकिन देश के कई इलाकों में अभी भी डिजिटल असमानता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्र आज भी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से वंचित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे इंटरनेट कनेक्शन, डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हर छात्र तक आसानी से पहुंच सकें। इससे शिक्षा में समान अवसर आएंगे और छात्रों को

बेहतर सीखने का मौका मिलेगा। शैक्षणिक सुविधाओं को आधुनिक बनाना जरूरी केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। मौजूदा शिक्षा संस्थानों में तकनीकी और आधुनिक संसाधनों की कमी है। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक रिसर्च लैब और तकनीकी उपकरणों से लैस कैंपस अब अनिवार्य हो गए हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बजट में इन सुविधाओं के लिए अलग से फंड आवंटित किया जा सकता है।

स्किल-बेस्ड शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए नए मेगा स्किल हब बनाए जाने की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में कोडिंग और डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। उच्च शिक्षा और शोध में विज्ञान स्ट्रीम के लिए अतिरिक्त सीटें दी जाएं। आईटीआई और अन्य तकनीकी संस्थानों को अपग्रेड करना जरूरी है और इंडस्ट्री के सहयोग से इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण (के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT और IIM में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि यहां आवेदन संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही, कंपनियों के उरफ फंड का एक हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शिक्षा खौफनाक नहीं, बल्कि स्नेह एवं हौसलों का माध्यम बने

आज जरूरत है शिक्षा को फिर से मानवीय बनाने की। ऐसी शिक्षा की, जिसमें स्नेह अनुशासन का आधार हो, संवाद दंड का विकल्प बने और विश्वास भय की जगह ले। बच्चों को यह एहसास कराया जाए कि वे जैसे हैं, वैसे ही स्वीकार्य हैं और उनकी प्रगति का रास्ता उनकी अपनी गति से तय होगा। शिक्षा को अहिंसक दृष्टि से देखना केवल नैतिक आग्रह नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता भी है। क्योंकि जिस समाज की शिक्षा बच्चों को तोड़ती है, वह समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। मासूमों को डर नहीं, हौसले का संबल चाहिए; डांट नहीं, दिशा चाहिए; और हिंसा नहीं, विश्वास चाहिए। तभी शिक्षा सचमुच जीवन देने वाली बन सकेगी, जीवन लेने वाली नहीं।

(लेखक- -ललित गर्ग)

जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा यदि भय, हिंसा और दमन का पर्याय बन जाए तो वह सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी। हाल के वर्षों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बढ़ते दबाव, घर और स्कूल में हिंसक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने शिक्षा की आत्मा पर गहरा आघात किया है। फरीदाबाद की उस हृदयविदारक घटना ने, जिसमें महज गिनती न सीख पाने के कारण एक मासूम बच्ची को पिता की क्रूरता ने मौत के मुंह में धकेल दिया, पूरे समाज को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस तरह खौफनाक होती पढ़ाई अब केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि जन-जन से जुड़ी विडम्बना बनती जा रही है। इस तथाकथित शिक्षा की विकृत मानसिकता का भयानक परिणाम है कि आज भी यह माना जाता है कि डर और मार से बच्चों को बेहतर बनाया जा सकता है। ज्ञान की इस सदी में यह सोचना ही शर्मनाक है कि पढ़ाई के नाम पर किसी बच्चे से उसका जीवन, उसका बचपन, उसका आत्मविश्वास छीना जा सकता है।

आज शिक्षा धीरे-धीरे मानवीय संवेदनाओं से कटती जा रही है। परीक्षा परिणाम, रैंक, अंक तालिका और प्रतिस्पर्धा के आंकड़े शिक्षा का चेहरा बनते जा रहे हैं। अभिभावक अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों के नाजुक कंधों पर लाद देते हैं और स्कूल उन्हें प्रदर्शन की मशीन मानकर आंकने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चा पढ़ाई को उत्सव या खोज की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक खौफनाक दायित्व के रूप में देखने लगता है। घर, जो सबसे सुरक्षित और स्नेहपूर्ण स्थान होना चाहिए, वहीं डर का अड्डा बन जाता है। स्कूल, जो जिज्ञासा और रचनात्मकता को पंख देने का माध्यम होना चाहिए, वह दंड और अपमान का स्थल बन जाता है। ऐसे में मासूम मन कहां जाए, किससे अपने भय और असहायता को साझा करे। मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के तमाम अध्ययन यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हिंसा, डांट, डर और अपमान बच्चों की सीखने की क्षमता को नष्ट करते हैं। डर के माहौल में बच्चा न तो प्रश्न पूछ पाता है, न प्रयोग कर पाता है और न ही अपनी गलतियों से सीख पाता है। उसकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और निर्णय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धीरे-धीरे वह हीनभावना का शिकार हो जाता है और स्वयं को अयोग्य समझने लगता है। यह कुंठा केवल बचपन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे जीवन उसके व्यक्तित्व पर छाया की तरह मंडराती रहती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी जोखिम लेने से डरते हैं, अपनी बात रखने में संकोच करते हैं और जीवन की प्रतिस्पर्धा में आत्मविश्वास के अभाव में पिछड़ जाते हैं। यह शिक्षा नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक शोषण है।

हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर बच्चे को एक ही मापदंड से आंकना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। किसी की रुचि गणित में है तो किसी की कला में, कोई खेल में खिलता है तो कोई संगीत या साहित्य में। प्रकृति ने हर बच्चे को किसी न किसी विशेष क्षमता के साथ भेजा है, लेकिन हम उसे पहचानने की बजाय एक तयशुदा पाठ्यक्रम और अपेक्षाओं की बेड़ियों में जकड़ देते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 ने बहुआयामी शिक्षा, रुचि आधारित सीख और मूल्यपरक दृष्टि की बात जरूर की है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी अंक और रैंक की मानसिकता हावी है। कोचिंग संस्कृति, बोर्ड परीक्षाओं का भय और प्रवेश परीक्षाओं की दौड़ ने शिक्षा को और भी संकीर्ण बना दिया है। इसके साथ ही यह भी एक कटु सत्य है कि कई बच्चे जन्मजात, आनुवंशिक या परिस्थितिजन्य कारणों से सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। दृष्टि दोष, श्रवण समस्या, डिस्लेक्सिया, मानसिक तनाव या पारिवारिक अस्थिरता जैसी स्थितियां उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे बच्चों को सबसे अधिक समझ, धैर्य और सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वही बच्चे सबसे पहले डांट और दंड का शिकार बनते हैं। शिक्षक और अभिभावक उनकी समस्या को समझने की बजाय उन्हें आलसी या अयोग्य ठहरा देते हैं। यह रवैया न केवल अमानवीय है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के साथ अन्याय भी है।

शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना है। यदि शिक्षा अहिंसा, करुणा, सहानुभूति और आत्मसम्मान का पाठ नहीं पढ़ाती, तो वह अधूरी है। बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी माध्यम उदाहरण होता है। जब वे घर और स्कूल में संवाद, धैर्य और प्रेम देखते हैं, तभी वे भी वही मूल्य आत्मसात करते हैं। भय के वातावरण में पले बच्चे या तो दब्बू बन जाते हैं या फिर हिंसा को ही समाधान मानने लगते हैं। समाज में बढ़ती असहिष्णुता और आक्रामकता के पीछे कहीं न कहीं वही शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है जो संवेदनशील मनुष्यों के बजाय केवल प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बार-बार परीक्षा के तनाव को कम करने और शिक्षा को जीवन से जोड़ने की अपील इस बात का संकेत है कि समस्या गंभीर है। लेकिन केवल भाषणों और नीतियों से बदलाव नहीं आएगा। असली परिवर्तन तब होगा जब अभिभावक यह समझेंगे कि उनका बच्चा उनकी प्रतिष्ठा का साधन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जब शिक्षक यह मानेंगे कि उनका दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि बच्चों में सीखने की ललक जगाना है। जब स्कूल प्रशासन दंड की संस्कृति छोड़कर सहयोग और परामर्श की व्यवस्था विकसित करेगा। और जब समाज यह स्वीकार करेगा कि असफलता भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई अपराध नहीं।

आज जरूरत है शिक्षा को फिर से मानवीय बनाने की। ऐसी शिक्षा की, जिसमें स्नेह अनुशासन का आधार हो, संवाद दंड का विकल्प बने और विश्वास भय की जगह ले। बच्चों को यह एहसास कराया जाए कि वे जैसे हैं, वैसे ही स्वीकार्य हैं और उनकी प्रगति का रास्ता उनकी अपनी गति से तय होगा। शिक्षा को अहिंसक दृष्टि से देखना केवल नैतिक आग्रह नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता भी है। क्योंकि जिस समाज की शिक्षा बच्चों को तोड़ती है, वह समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। मासूमों को डर नहीं, हौसले का संबल चाहिए; डांट नहीं, दिशा चाहिए; और हिंसा नहीं, विश्वास चाहिए। तभी शिक्षा सचमुच जीवन देने वाली बन सकेगी, जीवन लेने वाली नहीं।

नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस (एनपीएससी) भारत के 250 से ज्यादा प्रमुख प्राइवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का एक प्रमुख एसोसिएशन है, शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी और एनआईईपीए जैसे सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें पॉलिसी सुधार, पढ़ाने-सीखने के तरीकों और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। जिसका उद्देश्य शैक्षिक पहलों, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन और मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को बेहतर बनाना। इसी से जुड़ी डॉ. उषा राम भारतीय स्कूल शिक्षा क्षेत्र में एक अनुभवी शिक्षिका और लीडर हैं, इसी तरह श्रीनिवासन श्रीराम द मान स्कूल, दिल्ली के प्रिंसिपल हैं, जिनके पास रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल शिक्षा और आईटी एडमिनिस्ट्रेशन में 30 से ज्यादा सालों का अनुभव है। मेयो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के पूर्व हेड होने के नाते, वे आईसीटी इंटीग्रेशन और इक्कीसवीं सदी की लर्निंग में एक्सपर्ट हैं। इन दोनों शिक्षाशास्त्रियों से कल ही प्लेटीनम वैली इन्टरनेशनल स्कूल में नई शिक्षा नीति-2020 को लेकर सार्थक चर्चा हुई। सर्वसम्मति यही सामने आयी कि आज सबसे बड़ा और चिंताजनक प्रश्न यह है कि जो शिक्षा जीवन निर्माण, चरित्र गठन और मानवीय मूल्यों के संवर्धन का माध्यम होनी चाहिए थी, वही शिक्षा धीरे-धीरे विध्वंस का कारक क्यों बनती जा रही है।

जब शिक्षा सही दिशा में आगे नहीं बढ़ती, जब वह अहिंसा, करुणा, सह-अस्तित्व और नैतिक विवेक से संपन्न नागरिकों का निर्माण करने में विफल रहती है, तब उससे निकलने वाली पीढ़ियां केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी संकट का कारण बनती हैं।

संपादकीय

अति आशावाद से बचें

देश में आम बजट से पहले सामने आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला व गतिशील बनाने पर बल दिया गया है। यह सर्वेक्षण उन चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है, जिनके लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी के 7.4 रहने का भरोसा जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास वृद्धि दर के 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान में सीमापरक तनाव, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से यह सावधानीपूर्वक दर्शाया गया आशावादी दृष्टिकोण घरेलू मांग, उपभोग और निवेश की मजबूती को ही दर्शाता है। इसके बावजूद कि तमाम बाहरी जोखिम विद्यमान हैं, मसलन टैरिफ को लेकर आपूर्ति श्रृंखला में तनाव व देश की अपेक्षाओं का संतुलन बनाना शामिल है। यह सार्थक है कि सर्वेक्षण यथार्थवाद को नजरअंदाज नहीं करता है, जो यह भी दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पूंजी प्रवाह व मुद्रा की ताकत से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। यह भी हकीकत है कि एआई जैसी नई तकनीकों से होने वाले लाभ असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके लिये भी सहायक मानव संसाधन और विनियामक ढांचे की जरूरत होती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां श्रम शक्ति का बाहुल्य है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश होने का लाभ उठाएं। इसके लिये कौशल विकास को प्राथमिकता देने की सख्त जरूरत है, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों के जरिये विश्व में आर्थिक स्पर्धा का मुकाबला कर सकें। ये कदम हमारे निर्यात बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं। कालांतर में ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी अभियान को तरजीह देने से लेकर रणनीतिक लचीलेपन और रणनीतिक अनिवार्यता भारत की आर्थिक क्षमता की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की साख को अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाए। निस्संदेह, विश्व में भारतीय उत्पाद 'खरीदने के बारे में सोचने' से स्थिति को 'बिना सोचे भारतीय उत्पाद खरीदने' वाली सोच विकसित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इस स्थिति के लिये हमें विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता की सख्त जरूरत होगी। निस्संदेह, हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ संपन्न हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर अर्थव्यवस्था में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। सर्वेक्षण में इस बाबत कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस एफटीए के सिरे चढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी को कितना मिलता है। सवाल यह भी है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी के जीवन को बदलने में कितना मददगार होगा। एआई और तकनीक क्रांति के दौर में भारतीय विपुल श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है। भारत दुनिया में सबसे युवा श्रम शक्ति वाला देश है तो क्या हम उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप रोजगार देने में सक्षम होंगे, ताकि वे विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दे सकें।

वैश्विक आरोह अवरोह में सतर्कतापूर्वक आगे बढ़े,मजबूत भारत सतर्क भविष्य

(लेखक -कांतिलाल मांडोत)

- आर्थिक सर्वेक्षण 2026

लोकसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025- 26 देश की अर्थव्यवस्था का ऐसा दर्पण है जिसमें मजबूती आत्मविश्वास और सतर्कता तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यह दस्तावेज केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भारत की आर्थिक दिशा का संकेतक भी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार यह सर्वे बताता है कि वैश्विक उथल पुथल और भू राजनीतिक तनावों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी जड़ों में मजबूत बनी हुई है और आगे बढ़ने की क्षमता रखती है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है जबकि 2026 27 में यह 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता के बावजूद यह दर भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखती है। यह संकेत देता है कि घरेलू मांग मजबूत है निवेश का माहौल सुधर रहा है और नीतिगत सुधारों का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है।

सर्वेक्षण में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है। बीते कुछ वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों ने मध्यम अवधि की विकास क्षमता को लगभग सात प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। कर सुधार डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार बुनियादी ढांचे में भारी निवेश और वित्तीय अनुशासन ने मिलकर ऐसी स्थिति बनाई है जिसमें भारत बाहरी झटकों को अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से झेल सकता है। हालांकि सर्वे यह भी चेतावनी देता है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच सतर्क रहना जरूरी है और अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान देना होगा।

महंगाई के मोर्चे पर यह सर्वे आम लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच खुदरा महंगाई औसतन 1.7 प्रतिशत रही जो हाल के वर्षों में सबसे निचले स्तरों में से एक है। खास तौर पर सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट से घरेलू बजट पर दबाव कम हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां कई देश ऊंची महंगाई से जूझ रहे हैं वहीं भारत का यह प्रदर्शन उसकी मौद्रिक नीति और आपूर्ति प्रबंधन की सफलता को दर्शाता है।

सरकारी वित्त की स्थिति को लेकर भी सर्वे में सकारात्मक तस्वीर उभरती है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है और आने वाले वर्षों में इसे और कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह संकेत देता है कि सरकार खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने में सफल हो रही है। टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी खास तौर पर इनकम टैक्स दाताओं की संख्या का 9.2 करोड़ तक पहुंचना औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार का प्रमाण है।

सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। कुल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 53.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सर्विसेज और फाइनेंशियल सेवाओं के निर्यात ने भारत की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया है। शहरी रोजगार का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है जिससे शहरों में आय और उपभोग दोनों बढ़े हैं। यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन कर रहा है बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बदलाव साफ नजर आता है। भारत अब केवल कम लागत वाले उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि मध्यम और उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सर्वे के अनुसार इस क्षेत्र की लगभग 46.3 प्रतिशत गतिविधियां अब मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं। बिजली स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी से बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश को आर्थिक सर्वे ने विकास की गाड़ी का इंजन बताया है। केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च 2018 में 2.63 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 11.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सड़क रेलवे ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए इस निवेश ने न केवल निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दिया है बल्कि निजी निवेश के लिए भी अनुकूल माहौल बनाया है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत की आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक है जो करीब ग्यारह महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। यह भंडार वैश्विक बाजारों में अचानक आने वाले झटकों से निपटने की क्षमता देता है और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करता है।

रोजगार और गरीबी के मोर्चे पर भी सर्वे मिश्रित लेकिन सकारात्मक संकेत देता है। बेरोजगारी दर 2017 18 के 5.6 प्रतिशत से घटकर 2025 26 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है जो 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बदलाव है। गरीबी दर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है जो 2005 06 के 55.3 प्रतिशत से घटकर 2022 23 में 11.28 प्रतिशत रह गई है।

कृषि क्षेत्र को लेकर सर्वे में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। 2025 26 में कृषि विकास दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दर औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की तुलना में कम जरूर है लेकिन स्थिर है। सर्वे में उर्वरकों के असंतुलित उपयोग पर चिंता जताई गई है और यूरिया सब्सिडी को नकद हस्तांतरण से जोड़ने का सुझाव दिया गया है ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

आर्थिक सर्वे ने कुछ सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी रेखांकित किया है। जंक फूड की बढ़ती खपत को गंभीर समस्या बताते हुए इसके विज्ञापनों पर समय आधारित प्रतिबंध और पैकेट पर पोषण चेतावनी लेबल लगाने की सिफारिश की गई है। बच्चों में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को लेकर भी चिंता जताई गई है और आयु आधारित नियंत्रण तथा सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की जरूरत बताई गई है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सोने और चांदी की कीमतों में जारी तेजी पर भी ध्यान दिलाया है। यह तेजी केवल भू राजनीतिक तनावों का परिणाम नहीं बल्कि वैश्विक फिएट करेंसी पर घटते भरोसे का संकेत भी है। ऐसे में कीमती धातुएं सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में आगे भी आकर्षक बनी रह सकती हैं।

कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण 2026 भारत की अर्थव्यवस्था की एक संतुलित तस्वीर पेश करता है। इसमें आत्मसंतोष की जगह आत्मविश्वास है और अति उत्साह की जगह सतर्कता। सर्वे यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत को अल्पकालिक दबावों से विचलित हुए बिना दीर्घकालिक सुधारों और नवाचार के रास्ते पर चलते रहना होगा। फर्राटा और मैराथन दोनों एक साथ दौड़ने की यह चुनौती ही भारत की आर्थिक यात्रा का सार है।

(रु 103 जलवंत टाऊनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत -99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार ,साहित्यकार स्तम्भकार)

मुक्ति का मार्ग

पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म-मरण के चप्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैपुंड जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरणकमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह प्रकृति के तीन गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह परमपुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है।

जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत (चिन्मय आकाश) में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहां पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार के आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता।

विचार मंथन

कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रही हैं, केंद्र एवं राज्य सरकारें?

(लेखक-सनत जैन)

भारत की अर्थव्यवस्था आज जिस रास्ते पर बढ़ रही है, वहां एक सवाल बार-बार उठता है, क्या केंद्र और राज्य सरकारें अब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं? वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर करीब 27 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसमें लगभग 14 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 12-13 लाख करोड़ रुपये राज्य सरकारों ने कर्ज लिया है। आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 में यह आंकड़ा बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह स्थिति केवल उधारी बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के वित्तीय संतुलन, राजकोषीय घाटा की ओर वास्तविकता को दर्शा रही है। सरकारें मुख्य रूप से बॉन्ड जारी करके हर माह बाजार से पैसा जुटा रही हैं। कर्ज में लिए हुए पैसे से सरकारी योजनाओं में दी जाने वाली राशि एवं राज्य सरकारों के खर्च को पूरा किया जा रहा है। समस्या यह है, सरकारी बॉन्ड पर ब्याजदर यानी बॉन्ड यील्ड 6.6 से 6.7 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। जैसे-जैसे ब्याजदर बढ़ती है, सरकारों पर ब्याज भुगतान का बोझ भी बढ़ता जाता है। पिछले वर्षों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो कर्ज लिया गया है, उसको वापस लौटाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों को हर साल काफी बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। आज की स्थिति यह है, केंद्र सरकार अपने कुल राजस्व का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा कर्ज के ब्याज और भुगतान में खर्च कर रही है।

राज्य सरकारों की हालत इन दिनों बेहद नाजुक हैं। कई राज्यों में टैक्स से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में समाप्त हो रहा है। विकास योजनाओं या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उनके पास बहुत ही सीमित संसाधन बचते हैं। नतीजतन, राज्यों को फिर बॉन्ड जारी करके या वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर किसी तरह से भुगतान पूरे करने पड़ रहे हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब केंद्र सरकार योजनाओं का वित्तीय भार राज्यों के ऊपर डाल देती है। मनरेगा जैसी योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने से उन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। संसाधनों की कमी से जूझ रहे राज्य इस बोझ को उठाने के लिए कर्ज पर कर्ज लेते चले जा रहे हैं। जिसके कारण राज्यों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाती जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक पर भी दबाव साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में लाखों करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड भुगतान के लिए मैच्योर हो रहे हैं। इनका भुगतान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यह पूरा परिदृश्य खतरनाक रूप से आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। कर्ज लेकर कर्ज चुकाने की इस प्रवृत्ति पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो अगले कुछ ही वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाते देर नहीं लगेगी। इसका सबसे बड़ा बोझ आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। अब जरूरत है, सरकारें उधारी पर निर्भर विकास मॉडल से बाहर निकलकर, राजस्व बढ़ाने, राजस्व के अनुसार खर्चों पर नियंत्रण, अनुशासन और पारदर्शी वित्तीय नीति पर गंभीरता से काम करना होगा। कर्ज लेकर खर्च करने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। सरकार को अपने सभी विभागों में विकास कार्यों एवं खर्च में निगरानी बढ़ानी होगी। विकास कार्यों एवं सरकारी खर्चे में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना होगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। जनता को भी आर्थिक स्थिति की वास्तविकता का एहसास कराते हुए, लोक लुभावन स्कीमों से केंद्र एवं राज्य सरकारों को बचना होगा। कर्ज के आसरे अब भविष्य में वित्तीय स्थिति को संतुलित नहीं रखा जा सकता है। पिछले एक दशक में जिस तरीके से

टैक्स बढाए हैं, अब टैक्स बढ़ाने की भी स्थिति केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं की नहीं रही। यदि टैक्स बढ़ाकर सरकार खर्च पूरा करने की कोशिश करेगी, तो जनता इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। आम जनता भी कर्ज के बोझ से दबी हुई है। ऐसी स्थिति में सामाजिक, राजनीतिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया तीन पैसे की बढ़त के साथ ही के साथ ही 91.96 रुपये पर बंद हुआ। वहीं आज सुबह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर भारतीय मुद्रा पर दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से संभलते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नौ पैसे मजबूत होकर 91.90 पर पहुंच गया। गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 91.99 के स्तर पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपये में यह सुधार सीमित रहा। मजबूत डॉलर और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी के कारण भारतीय मुद्रा पर दबाव बना रहा, जिससे रुपये को बड़ी मजबूती नहीं मिल सकी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 91.89 पर खुला और शुरुआती सौदों में 91.87 तक मजबूत हुआ। बाद में यह 91.90 पर कारोबार करता दिखा। इस दौरान छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स 0.36 फीसदी की बढ़त के साथ 96.48 पर बना रहा, जिसने रुपये की चाल को प्रभावित किया।

फेसबुक इंडिया का 2024-25 का लाभ बढ़कर 647 करोड़ हुआ

नई दिल्ली । फेसबुक इंडिया ने मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में एकल आधार पर लगभग 647.45 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 28 प्रतिशत अधिक है। टोफलर ने कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी सूचना के आधार पर यह जानकारी दी। फेसबुक इंडिया ने एक साल पहले 504.93 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। इस दौरान उसका परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 3,792.91 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का कुल खर्च 2,881 करोड़ रुपये बताया गया है। मेटा के स्वामित्व वाली फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी खर्च समीक्षाधीन अवधि में 36 प्रतिशत बढ़कर 648.57 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 476 करोड़ रुपये था। कंपनी का कर व्यय वित्त वर्ष 2023-24 के 209.2 करोड़ रुपये से 46 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 305.18 करोड़ रुपये हो गया।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 2,000 करोड़ की पुणे में जमीन खरीदी

नई दिल्ली । रियल्टी फर्म गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने पुणे में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व वाली आवास परियोजना के निर्माण के लिए 8.5 एकड़ भूमि खरीदी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने पुणे के महालुंगे में सीधे खरीद के माध्यम से 8.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने कहा कि प्रस्तावित विकास में मुख्य रूप से समूह आवास परियोजना शामिल होगी और इसमें लगभग 21 लाख वर्ग फुट की विकास क्षमता होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 2,000 करोड़ रुपये होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज के एक अे धिकारी ने कहा कि पुणे भारत के सबसे जीवंत शहरी केंद्रों में एक है, जो मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक केंद्रों से प्रेरित है।

मुनाफा वसूली के कारण सोना-चांदी की जमकर हुई बिकवाली...

सटोरियों के कारण गड़बड़ाया गणित... बढ़ोत्तरी का बुलबुला अचानक फूट गया ...

85,000 सस्ती हुई चांदी, सोना भी धड़ाम

नई दिल्ली। सोना और चांदी अब सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि आम आदमी भी सोना और चांदी में निवेश करने में लगे हुए हैं। लेकिन शुक्रवार को अचानक चांदी और सोने के भाव में तगड़ी गिरावट आई है। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से 85000 रुपये गिर चुकी है, जबकि सोने के भाव में 25000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है। इतनी बड़ी गिरावट तब आई है, जब चांदी 4.20 लाख रुपये और सोना 2 लाख रुपये के करीब पहुंच गए थे। शुकवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मार्च वायदा के लिए 1 किलो चांदी की कीमत करीब 65000 रुपये गिरकर 3,35,001 रुपये पर पहुंच गई थी, लेकिन गुरुवार की शाम को चांदी कीमत बढक़र 4,20,048 रुपये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थी। इस हिसाब से देखें तो 24 घंटे में ही चांदी के भाव में करीब 85,000 रुपये की गिरावट आई है। इसी तरह, सोने की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। सोना 29 जनवरी, गुरुवार को अपने रिकॉर्ड स?तर 1,93,096 रुपये पर था, लेकिन शुक्रवार को यह 16000 रुपये टूटकर 1,67,406 रुपये पर आ गया। यानी 24 घंटे के दौरान सोने में 25,500 रुपये की गिरावट आई है।जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल सामान्य नहीं है। बाजार में हर दिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, वह केवल मांग या सट्टेबाजी का नतीजा नहीं है। इसके पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी करवट है, जो आने वाले समय में हम सब की जेब पर गहरा असर डाल सकती है। यह संकेत है एक बड़े बदलाव का, जिसे आर्थिक विशेषज्ञ डी डॉलराइजेशन का नाम दे रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया अब अमेरिकी डॉलर के मोहपाश से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो अमेरिका की वह सुपरपावर वाली छवि हमेशा के लिए धूमिल हो सकती है, जो दशकों से डॉलर की ताकत पर टिकी थी। वायदा बाजार में गुरुवार को चांदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए 4 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा ना सिर्फ पार किया, बल्कि वहां से भी इसमें जबरदस्त उछाल आई थी। चांदी का भाव गुरुवार को 34,000 रुपये चढक़र अपने ऑल टाइम हाई लेवल 4,20,048 रुपये पर पहुंच गई थी। इसी तरह, वायद बाजार 29 जनवरी को सोना 16000 रुपये चढक़र अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 1,93,096 रुपये पर पहुंच गया था। हालांकि अब इन दोनों कीमती धातुओं में तगड़ी गिरावट आई है।

मुनाफावसूली के कारण गिरावट

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मुनाफावसूली है, क्योंकि कई दिनों से सोने और चांदी के भाव तेजी देखी जा रही थी और इनकी कीमतें हर दिन रिकॉर्ड स्तर बना रही थीं। चांदी ने तो कुछ ही हफ्ते में 3 लाख रुपये से 4 लाख रुपये का लेवल पार कर लिया था। वहीं सोने ने भी खूब तेजी दिखाई है। ऐसे में अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं । कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि सोने और चांदी में जैसे ही बिकवाली हावी हुई वैसे ही शॉर्ट सेलर एंटर हो गए और ट्रेडिंग के दौरान सिल्वर को शॉर्ट किया, जिस कारण इसके दाम में भारी गिरावट आई है।

ईयू के साथ एफटीए से भारतीय निर्यातकों को मिलेगा बड़ा बाजार: मूडीज

- भारतीय निर्यातकों को बड़े और स्थिर बाजार तक पहुंच मिलेगी

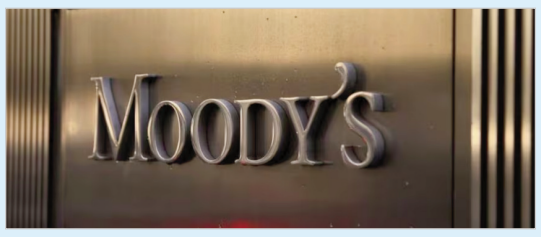

नई दिल्ली । भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा 27 जनवरी को की गई। इसे इस साल हस्ताक्षरित और लागू किए जाने की संभावना है। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि यह समझौता भारत के व्यापारिक संबंधों को विविध बनाने में मदद करेगा। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए शुल्क और व्यापारिक अस्थिरता के बीच भारतीय निर्यातकों को बड़े और स्थिर बाजार तक पहुंच मिलेगी। इससे भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति को मजबूती मिलेगी। मूडीज ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के लिए यह समझौता तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने में सहायक होगा। एफटीए लागू होने के बाद व्यापार की मात्रा बढ़ेगी, व्यापार प्रवाह में विविधता आएगी और स्थिर बाजार उपलब्ध होंगे। इस समझौते से दोनों पक्षों की आर्थिक साख मजबूत होगी और वैश्विक व्यापार में उनकी स्थिति बेहतर होगी।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 296, निफ्टी 98 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी होने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 296.59 अंक टूटकर 82,269.78 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 98.25 अंक फिसलकर 25,320.65 पर बंद हुआ। आज सबसे अधिक गिरावट धातु शेयरों में रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स 5.21 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी कमोडिटीज 2.13 फीसदी, निफ्टी आईटी 1.03 फीसदी, निफ्टी पीएसई 0.90 फीसदी और निफ्टी सर्विसेज 0.64 फीसदी की गिरावट पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी मीडिया 1.85 फीसदी, निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.43 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी 1.37 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.08 फीसदी, निफ्टी रियल्टी 0.84 फीसदी, निफ्टी ऑटो 0.73 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। वहीं लार्जकैप की जगह पर मिडकैप और स्मॉलकैप में मिश्रित कारोबार हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 109 अंक या 0.19 फीसदी की कमजोरी के साथ 58,432 अंक और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 54.10 अंक या 0.32 फीसदी बढ़त के साथ ही 16,879.10 पर था।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, एसबीआई, आईटीसी, बीईएल, एचयूएल, टाइटन, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों को लाभ हुआ जबकि टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट और टीसीएस के शेयर नीचे आये। बाजार जानकारों के अनुसार आम बजट से पहले भारतीय बाजार में ये उतार-चढ़ाव धातु शेयरों में बिकवाली हावी होने से आई है। इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ 81,947 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी भी कमजोर शुरुआत के साथ ही 25,247 अंक पर खुलने के बाद 138.05 अंक गिरकर 25,280 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। निवेशक आगामी केंद्रीय बजट 2026 को लेकर फिलहाल सतर्क नजर आये । वित्त मंत्री 1 फरवरी, रविवार को बजट पेश करेंगी। बजट से पहले अनिश्चितता के माहौल में निवेशक जोखिम लेने से बचते दिखे, जिसका असर बाजार पर साफ नजर आया। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती आई है। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.25 फीसदी, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.05 फीसदी और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 इंडेक्स 0.20 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर अमे रिकी बाजार में मिलाजुला कारोबार रहा।

भारत का बजट अब सिर्फ घरेलू दस्तावेज नहीं! न्यूयॉर्क से लंदन तक दिखेगा असर

आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अनुमान, भारत की विकास दर 2026-27 में 6.5-7 फीसदी रहेगी

नई दिल्ली ।

दुनिया युद्ध, महंगाई और उच्च ब्याज दरों जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें ऊंची हैं, चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त है, और पश्चिम एशिया व यूक्रेन में संघर्ष जारी है।

ऐसे माहौल में भारत का बजट सिर्फ घरेलू दस्तावेज नहीं, बल्कि वैश्विक निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए स्थिरता का संकेतक बन गया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भारत 2026 -27 में 6.5-7 फीसदी की विकास दर बनाए रख सकता है। ये एजेंसियां विशेष रूप से राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय, रक्षा और सामाजिक योजनाओं पर ध्यान दे रही हैं।

विदेशी निवेशक भी यह देख रहे हैं कि भारत कैसे निवेश-अनुकूल माहौल बनाए रखता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और ग्रीन एनर्जी में। विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित बजट पेश करना भारत के लिए वैश्विक स्थिरता का संदेश होगा। यदि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास पर खर्च बढ़ाया गया, तो भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मॉडल भी बनेगा। वहीं आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव अभी भी भारत के लिए जोखिम बने रहेंगे। भारत का बजट अब घरेलू योजना से आगे बढ़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकेतक बन गया है।

इंडिया पावर कॉरपोरेशन भूटान में 70 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करेगी

कोलकाता ।

इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) ने शुक्रवार को कहा कि भूटान के पारो जिले में 70 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए पड़ोसी देश की ग्रीन एनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना उसकी अगले पांच वर्षों में भूटान में 1.5 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने की योजना का हिस्सा है। इसमें कहा गया कि भूटान की बिजली मांग अगले दो वर्षों में दोगुनी से अधिक होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण गेलेफू माइंडफुल सिटी जैसी परियोजनाएं, फेरोसिलिकॉन सहित ऊर्जा-गहन उद्योगों का विस्तार और डिजिटल बुनियादी ढांचे तथा क्रिप्टो-माइनिंग गतिविधियों से बढ़ती मांग है। भूटान के ऊर्जा उत्पादन में जलविद्युत का दबदबा कायम है, लेकिन देश ने 2034 तक 25,000 मेगावाट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है। आईपीसीएल के अनुसार तकनीकी मानकों के प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद पारो में तेनचुका का चयन किया गया था।

वैश्विक रक्षा खर्च रिकॉर्ड स्तर पर, अमेरिका सबसे आगे

- भारत चौथे स्थान पर है, रक्षा बजट 75 बिलियन डॉलर

नई दिल्ली ।

2025 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक रक्षा खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 में यह लगभग 2,718 बिलियन डॉलर (2.7 ट्रिलियन यूएसडी) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। इस बढ़ोतरी के मुख्य कारणों में रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव और यूरोप में सुरक्षा चिंताएं शामिल हैं। अमेरिका सबसे बड़े रक्षा बजट वाला देश है, जिसका खर्च लगभग 895 बिलियन डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा मिसाइल, नौसेना और एयरोस्पेस तकनीक पर लगाया जाता है। चीन दूसरे स्थान पर है, जिसका बजट 266.85 बिलियन डॉलर है और यह आधुनिक हथियार, समुद्री और वायु शक्ति को मजबूत करने पर केंद्रित है। रूस का बजट 126 बिलियन डॉलर है, जिसे यूरोप में अपनी सैन्य प्रभावशीलता बनाए रखने और वायु-समुद्री बलों के लिए रखा गया है। भारत चौथे स्थान पर है, जिसका बजट 75 बिलियन डॉलर है। भारत इसे सैनिक, मिसाइल प्रणालियों, वायु और नौसेना बलों के आधुनिकीकरण में खर्च कर रहा है। कई देशों का रक्षा बजट उनकी जीडीपी का 2 फीसदी से अधिक है। अमेरिका का यह आंकड़ा लगभग 3.4 फीसदी है, जबकि रूस और सऊदी अरब में यह प्रतिशत और भी अधिक है। यूरोप और मध्य पूर्व के कई देश भी अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण बड़े हिस्से का बजट रक्षा पर लगाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में कई देशों, विशेषकर भारत, अपने रक्षा बजट को और बढ़ाएंगे। इसका फोकस तकनीकी आधुनिकीकरण, मिसाइल और एयरोस्पेस विकास, और रक्षा निर्यात पर होगा। वैश्विक सुरक्षा चुनौतियाँ और भू-राजनीतिक तनाव आने वाले वर्षों में रक्षा खर्च में वृद्धि को प्रेरित करते रहेंगे।

महिंद्रा बीई 6 की बैटरी और मोटर को कंपनी ने बताया पूर्ण सुरक्षित

नई दिल्ली ।

बीते दिनों उत्तरप्रदेश के कुराना टोल प्लाजा के पास चलती महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी में अचानक आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कंपनी ने अब इस पर आधिकारिक बयान जारी किया है। महिंद्रा ने बताया कि मौके पर की गई विस्तृत जांच, ऑनबोर्ड सेंसर डेटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स के विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि हाई-वोल्टेज बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर पूरी तरह सुरक्षित थीं और आग लगने का कारण नहीं बनीं। कंपनी के अनुसार, सभी सेफ्टी सिस्टम डिजाइन के अनुरूप काम कर रहे थे, जिससे ड्राइवर और वाहन में सवार सभी लोग बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकल सके। जांच में सामने आया कि गाड़ी में टायर के अधिक तापमान का अलर्ट पहले ही जारी हो गया था, जिसके बाद ऑटोमैटिक सेफ्टी फीचर्स सक्रिय हुए। इनमें वाहन की स्पीड कम करना और सिस्टम को कंट्रोल्ड तरीके से बंद करना शामिल था, जिससे गाड़ी सुरक्षित रूप से रुक गई। महिंद्रा के अनुसार, बाहरी गर्मी और तनाव के बावजूद बैटरी को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसके सभी हेल्थ पैरामीटर तय सीमा के भीतर पाए गए। कंपनी ने यह भी बताया कि डेटा से संकेत मिला है कि पिछले दाहिने टायर के पूरी तरह पंक्चर होने के बावजूद गाड़ी को करीब 10 मिनट तक लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया।

इस दौरान ईएसपी और टीसीएस सिस्टम लगातार व्हील स्पिन को कंट्रोल करने में लगे रहे। टायर और सड़क के बीच बढ़े घर्षण के कारण ज्यादा तापमान पैदा हुआ, जिससे रबर में आग लगी।

महिंद्रा ने दोहराया कि गुणवत्ता और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मालूम हो कि देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा की मौजूदगी तेजी से मजबूत हुई है, जिसमें उसकी नई फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवीएस एक्सईवी 9ई और बीई 6 की अहम भूमिका रही है।

कच्चे तेल में नरमी से डॉलर के मुकाबले नौ पैसे मजबूत

- गुरुवार को रुपया 91.99 के स्तर पर बंद हुआ था

मुंबई ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर शुक्रवार को भारतीय मुद्रा पर दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से संभलते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नौ पैसे मजबूत होकर 91.90 पर पहुंच गया। गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 91.99 के स्तर पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपये में यह सुधार सीमित रहा। मजबूत डॉलर और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी के कारण भारतीय मुद्रा पर दबाव बना रहा, जिससे रुपये को बड़ी मजबूती नहीं मिल सकी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 91.89 पर खुला और शुरुआती सौदों में 91.87 तक मजबूत हुआ। बाद में यह 91.90 पर कारोबार करता दिखा। इस दौरान छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 96.48 पर बना रहा, जिसने रुपये की चाल को प्रभावित किया।

किआ इंस्पायरिंग ड्राइव प्रोग्राम पुनः लॉन्च

नई दिल्ली ।

कार निर्माता कंपनी किआ इंडिया ने किआ इंस्पायरिंग ड्राइव (के आईडी) प्रोग्राम पुनः लॉन्च किया है। भारत में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत नई किआ सेल्टोस से की गई है और कंपनी आने वाले समय में इसे चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी कनेक्टेड कारों में उपलब्ध कराएगी।ग्राहक इस फीचर का इस्तेमाल किआ कनेक्ट ऐप के जरिए कर सकेंगे, जिससे ड्राइविंग से जुड़ी अहम जानकारियां आसानी से मिलेंगी। किआ इंस्पायरिंग ड्राइव प्रोग्राम एक एडवांस ड्राइविंग स्कोर सिस्टम है, जो रियल-टाइम में ड्राइवर की आदतों का विश्लेषण करता है।

यह सिस्टम तेज एक्सेलेरेशन, अचानक ब्रेकिंग और अचानक स्टार्ट जैसी गतिविधियों के आधार पर ड्राइविंग पैटर्न को परखता है और यह बताता है कि ड्राइवर कितनी सुरक्षित और संतुलित तरीके से गाड़ी चला रहा है। खास बात यह है कि केआईडी स्कोर तीन महीने के रोलिंग एवरेज पर आधारित होता है, जिससे किसी एक दिन की ड्राइविंग का असर पूरे स्कोर पर नहीं पड़ता और लंबे समय की ड्राइविंग आदतों की सही तस्वीर सामने आती है। यह प्रोग्राम सिर्फ सेफ्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे इंटरैक्टिव और एंगेजिंग भी बनाया गया है।

किआ ग्राहक अपनी ड्राइविंग प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, रैंकिंग हासिल कर सकते हैं और कम्युनिटी लीडरबोर्ड पर अन्य ड्राइवर्स से तुलना कर सकते हैं। इससे सुरक्षित ड्राइविंग को एक तरह का कम्युनिटी अनुभव बनाया गया है, जहां लोग एक-दूसरे से सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित होते हैं। किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अतुल सूद ने कहा कि सेफ्टी किआ की फिलॉसफी का अहम हिस्सा है। केआईडी प्रोग्राम ग्राहकों को डेटा-आधारित फीडबैक देकर उन्हें ज्यादा जिम्मेदार और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करता है।

बैंक निफ्टी पर बुलिश दाव, बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी से मुनाफे की उम्मीद

नई दिल्ली । शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच बैंक निफ्टी को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हालात बैंक निफ्टी में आगे और तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शन डेटा के साथ-साथ तकनीकी चार्ट भी मजबूती दिखा रहे हैं। ट्रेडर्स बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटजी अपना सकते हैं। इसके तहत 24 फरवरी 2026 की एक्सपायरी वाले 60500 कॉल ऑप्शन को 726 पर खरीदने और 61000 कॉल ऑप्शन को 511 रुपए पर बेचने की सलाह दी गई है। इस रणनीति में प्रति यूनिट 215 रुपए का खर्च आता है। एक लॉट (30 यूनिट) में कुल निवेश करीब 6,450 रुपए बनता है। अगर एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 61000 या उससे ऊपर बंद होता है, तो इस ट्रेड से 8,550 रुपए तक का अधिकतम मुनाफा संभव है। इस रणनीति का ब्रेक-ईवन लेवल 60715 रखा गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक 1:1.33 का रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो इसे संतुलित बनाता है। इस ट्रेड के लिए करीब 36,000 रुपए के मार्जिन की जरूरत होगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत- न्यूजीलैंड के बीच आज होगा पांचवां और अंतिम टी20

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को होने वाले पांचवें और अंतिम टी20 मैच में जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ने पहले ही शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज जीत ली है। ऐसे में उसपर कोई दबाव भी नहीं रहेगा। भारतीय टीम को चौथे टी20 में लक्ष्य का पीछा करते हुए हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम अपनी इस कमजोरी को इस मैच में दूर करना चाहेगी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस सीरीज में अच्छा रहा है पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अब तक सीरीज में असफल रहे हैं। सैमसन अब अपने घरेलू मैदान पर बड़ी पारी खेलकर अगले माह होने वाले टी20 विश्वकप से पहले लय हासिल करना चाहेंगे। इसी कारण सभी की नजरें उनपर रहेंगी। वहीं अगर सैसमन इस मैच में रन नहीं बना पाते हैं तो विश्कप में उन्हें टीम में शायद ही जगह मिले। इससे पहले चौथे टी20 मैच में भारतीय टीम ने पांच मुख्य गेंदबाजों को ही खिलाया था और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं करवाई। भारतीय टीम ये मैच हार गयी है। ऐस में अंतिम मैच में एक बार फिर गेंदबाजी संयोजन में बदलाव किया जा सकता है। इस मैच में एक बार फिर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अवसर मिल सकता है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल नागपुर में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उंगली में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं उन्हें भी फिट होने पर इस मैच में जगह मिल सकती है।

अब तक सीरीज में किये प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम इस सीरीज में जीत की प्रबल दावेदार बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर कीवी टीम भी इस मैच ो जीतकर विश्वकप से पहले अपनी लय और मनोबल को बढ़ाना चाहेगी।, पिछले मैच में उसके गेंदबाज और बल्लेबाज सफल रहे थे जिससे उसका हौंसला बढ़ेगा।

विशाखापत्तनम में भारतीय टीम के केवल शिवम दुबे ही कीवी गेंदबाजों के सामने टिक पाये थे। यहां के मैदान की बात करें तो

इसमें बड़े स्कोर बने हैं। भारतीय टीम ने यहां खेले गए अपने चार टी20 मैचों में से तीन जीते हैं, जिसमें 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता गया एक मैच भी शामिल है। वहीं मेहमान टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, हम जानते हैं कि भारतीय टीम को हराने के लिए क्या करने की जरुरत है। ऐसे में यहां एक रोमांचक मुकाबला होना तय है। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट के टीम में शामिल होने से भी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बेहतर हुई है। टीम को हालांकि अपनी गेंदबाजी बेहतर करनी होगी। इस मैच में कीवी टीम फिट होने पर अपने मुख्य तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को भी शामिल कर सकती है।

टीम इस प्रकार है

भारत = सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह , वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड =मिशेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।

ऑस्ट्रेलियाइ ओपन : गैडेकी और पीयर्स ने मिश्रित युगल खिताब जीता

मेलबर्न (एजेंसी)। स्थानीय खिलाड़ी ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। गैडेकी और पीयर्स की जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडेनोविक और मैनुअल गिनार्ड को 4-6, 6-3, 10-8 से हराया। गैडेकी और पीयर्स साल 1988-89 में जाना नोवोत्ना और जिम पुघ के बाद मिश्रित युगल खिताब बरकारार रखने वाली पहली जोड़ी बन गईं है। ये जोड़ी साल 1963-64 में मार्गरेट कोर्ट और केन फ्लेचर के बाद अपने घरेलू स्लैम में लगातार खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी है। गैडेकी ने ट्रॉफी के एक समारोह में इस जीत पर खुशी जतायी है।

इस जीत के साथ ही पीयर्स ने तीसरा मिश्रित युगल खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने साल 2022 में स्टॉर्म सैंडर्स के साथ अमेरिकी ओपन भी जीता था। वहीं उन्होंने साल 2017 में फिनलैंड के हेनरी कोंटिनेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल जीता था। इसके अलावा मैथ्यू एब्डेन के साथ जोड़ी बनाकर 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरी ओर ये गैडेकी का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने साल 2025 में पीयर्स के साथ मेलबर्न पार्क में जीत हासिल की थी।

डिकॉक के शतक से दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 में वेस्टइंडीजी को सात विकेट से हराया

सुपरस्पोर्ट पार्क (एजेंसी)। क्विंटन डिकॉक की शतकीय पारी की सहायता से मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने यहां दूसरे अंतरराष्ट्रीय टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 221 रन बनाये। इसके बाद जीत के लिए मिले इस लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीक ने डिकॉक की आक्रामक पारी की सहायता से 17.3 ओवर में ही 225 रन बनाकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस जीत के साथ ही 220 से ज्यादा रनों का सबसे तेजी से पीछा करने का रिकार्ड भी अपने नाम किया है। इससे पहले कोई भी टीम इतने कम ओवरों में इतना स्कोर नहीं बना पायी है। वहीं टी20 अंतरराष्ट्रीय में ये दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका की टीम इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पायी है। साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ 259 रन के लक्ष्य का पीछा कर जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के हीरो डिकॉक रहे। डिकॉक ने 49 गेंदों में 10 छक्के और 6 चौके लगाकर 115 रन बनाये। डिकॉक ने पारी की शुरुआत के साथ ही हमले शुरु कर दिये। उनका रेयान रिकेल्टन ने भी नाबाद 77 रन बनाकर अच्छा साथ दिया। उन्होंने केवल 36 गेंदों में तीन छक्के और 9 चौके लगाकर 77 रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिकॉक और रिकेल्टन के बीच 162 रन की साझेदारी हुई। ये इस पारी में किसी भी विकेट के लिए दक्षिण अफ्रीका की ओर से चौथी सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है. डिकॉक का यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा शतक है! मैच के बाद डिकॉक ने बताया कि 44 गेंदों में यह शतक उन्होंने उधार लिए बल्ले से बनाया। डिकॉक ने कहा, ' वह अपना बल्ला घर पर ही भूल गये थे। इसके बाद उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस से बल्ला मांगा था।' डिकॉक ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम ने ब्रैंडन किंग के 49 और सिमरन हेटमायर के 75 रनों की सहायता से दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में ही 126 रन की मजबूत साझेदारी बनायी। वहीं शेरफेन रदरफोर्ड ने 24 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाये। वहीं दक्षिण अफ्रीका की ओर से स्पिनर केशव महाराज ने 4 ओवर में 2 विकेट लेकर 22 रन दिए।

अंडर-19 विश्व कप : भारत-पाकिस्तान के सुपर सिक्स मुकाबले से तय होगी सेमीफानल की टीमें

बुलवायो (एजेंसी)। आईसीसी अंडर-19 विश्वकप सुपर सिक्स मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच एक फरवरी को यहां के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला होगा। इसमें जीत के साथ ही दोनो ही टीमें सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी पक्की करना चाहेंगी। इस प्रतियोगिता के दूसरे दौर में क्वालीफाई करने वाली 12 टीमों में से पांच टीमें सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गयी है। वहीं अब ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जबकि जबकि ग्रुप 2 से भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान ग्रुप 2 सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड दोनो ही टीमें छह-छह अंक लेकर शीर्ष पर हैं पर बेहतर रन रेट के कारण भारतीय टीम पहले जबकि इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

अगर भारतीय टीम जीतती है या मैच का कोई परिणाम नहीं निकलता है तो पाकिस्तान टीम पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएग। वहीं अगर पाकिस्तान बड़ी जीत हासिल करता है, तो भारतीय टीम के भी बाहर होने की संभावना है। हालांकि, अगर उनकी जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता, तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही क्वालीफाई कर जाएंगे। ग्रुप 2 की तीनों दावेदार टीमों के सुपर सिक्स चरण में अभी एक-एक मैच होना है। ऐसे में इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से 30 जनवरी को होगा। भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ में आगे हैं, वहीं पाक की संभावनाएं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मैच के परिणाम पर निर्भर रहेंगी। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं अगर भारतीय टीम पाकिस्तान को हराया देती है या बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो भी इंग्लैंड नॉकआउट में पहुंच जाएगी। वहीं पाकिस्तान के पास भी अवसर हैं पर लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी जीत हासिल करनी होगी। वहीं अगर इंग्लैंड कीवी टीम से हार जाती है तो इंग्लैंड के नेट रनरेट में गिरावट आएगी और ऐसे में उनहें भारत और पाक मैच के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड हो पीछे छोड़ सकती है।

एमबापे के दो गोल के बावजूद हारा रियाल मैड्रिड, बार्सिलोना आगे बढ़ा

लंदन । स्टार स्ट्राइकर काइलियन एमबापे के दो गोल के बावजूद रियाल मैड्रिड को चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट में बेनफिका से 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच से पहले रियाल मैड्रिड 36 टीमों की तालिका में तीसरे स्थान पर था लेकिन अब वह नौवें स्थान पर खिसक गया जो अंतिम 16 में सीधे प्रवेश पाने से एक स्थान नीचे है। बेनफिका की तरफ से यूक्रेन के गोलकीपर अनातोली ट्रूबिन ने इंजरी टाइम के आठवें मिनट में गोल किया। इससे बेनफिका गोल अंतर के आधार पर 24वें स्थान पर पहुंच गया और उसने प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित कर ली। अनातोली ने जब गोल किया तब रियाल मैड्रिड नौ खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। इससे कुछ मिनट पहले ही राउल असेंसियो और रोड्रिगो को लाल कार्ड दिखाए गए थे। स्पोर्टिंग लिस्बन ने एथलेटिक बिलबाओ के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की, जिससे रियाल मैड्रिड शीर्ष आठ से बाहर हो गया। स्पोर्टिंग ने अप्रत्याशित रूप से लिवरपूल, टॉटेनहम, बार्सिलोना, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के साथ शीर्ष आठ में जगह पक्की कर ली। तालिका में शीर्ष पर काबिज आर्सेनल ने कैरात अल्माटी को 3-2 से हराकर लगातार आठवीं जीत दर्ज कीं। वह और दूसरे स्थान पर काबिज बायर्न म्यूनिख पहले ही मार्च में शुरू होने वाले राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए थे।

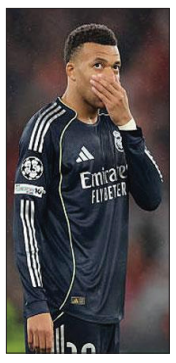

सीमित ओवरों के क्रिकेट में जगह बनाना चाहते हैं सरफराज

मुंबई । बल्लेबाज सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी अब भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाये हैं। सरफराज का सपना सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम में जगह बनाना है। उन्हे अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुछ अवसर मिले जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके बाद भी उन्हें बाहर कर दिया गया। अब इस क्रिकेट का लक्ष्य अपने प्रदर्शन से वापसी करना है। इस क्रिकेटर ने कहा कि वह अपने प्रदर्शन और फिटने को बेहतर करने पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही कहा कि वह भारतीय टीम के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में खेलना चाहते हैं और उसी को देखते हुए तेजी से रन बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।' आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) टीम में शामिल किये जाने से भी वह उत्साहित हैं। साथ ही अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्हें धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से भी खुशी हुई है. इस बल्लेबाज ने कहा, 'मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीएसके के लिए खेल पाऊंगा। मेरा सपना इस पीढ़ी के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलने का था।' उन्होंने कहा, 'विराट भाई के साथ मैंने आरसीबी में खेला। रोहित भाई के साथ कभी नहीं खेला था और मुझे नहीं लगा था कि मौका मिलेगा पर फिर टेस्ट टीम में उनके साथ खेला।' उन्होंने कहा, 'धोनी भाई के संन्यास के बाद लगा था कि उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा पर नीलामी के पहले दौर में किसी के बोली नहीं लगाने के बाद सीएसके ने उन्हें शामिल किया है। जिससे उन्हें अब उनके साथ खेलने का अवसर मिल जाएगा।'इस क्रिकेटर ने कहा , 'मैं हमेशा वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं। अतीत में कुछ नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता कल क्या होगा।' घरेलू क्रिकेट में कुछ समय तक उनकी फॉर्म ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, अपनी फिटनेस और खेल पर काम किया जिससे अब वह फिर से रन बना रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन: कार्लोस अल्काराज ने एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई

मेलबर्न (एजेंसी)। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने शुक्रवार को यहां पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बनाई। इस तरह से 22 साल के अल्काराज चारों ग्रैंड स्लैम पर प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अब उनका लक्ष्य करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनना होगा।

अल्काराज को पांव में ऐंठन और खिंचाव के कारण पिछले साल के उपविजेता ज्वेरेव की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा लेकिन आखिर में वह पांच घंटे 27 मिनट में 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 से जीत हासिल करने में सफल रहे। स्पेन के खिलाड़ी अल्काराज ने अच्छी शुरुआत की लेकिन पहले दो सेट जीतने के बाद वह अगले दो सेट में टाइब्रेकर में हार गए। ज्वेरेव पांचवें और निर्णायक सेट में एक समय मैच के लिए सर्विस कर रहे थे लेकिन अल्काराज ने ब्रेक प्वाइंट लेकर वापसी की और फिर इसके बाद जर्मनी के अपने प्रतिद्वंद्वी को मौका नहीं दिया।

अल्काराज का फाइनल में मुकाबला दो बार के मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर या 10 बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता नोवाक जोकोविच से होगा, जो 25वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अल्काराज ने जिस तरह से शुरुआत की थी उससे लग रहा था कि वह आसानी से जीत हासिल कर लेंगे लेकिन तीसरे सेट के नौवें गेम में वह लंगड़ाने लगे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें दाहिने पैर के ऊपरी हिस्से में कोई समस्या है।

जब अपने प्रतिद्वंद्वी को इलाज के लिए तीन मिनट का ब्रेक दिया गया, तो ज़्वेरेव स्पष्ट रूप से परेशान दिखे। तब तीसरी वरीयता प्राप्त यह खिलाड़ी टूर्नामेंट के एक अधिकारी से बात कर रहा था। अल्काराज ने इसके बाद 6-5 से बढ़त बना दी जिसके बाद उन्हें फिर से अपने पांव की मालिश करवानी पड़ी। ज्वेरेव हालांकि इस सेट को टाइब्रेकर तक खींचने में सफल रहे जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। चौथे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला लेकिन ज्वेरेव टाइब्रेकर में फिर से कामयाब रहे और इस तरह से उन्होंने मैच को बराबरी पर ला दिया।

चार घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद मैच पांचवें सेट में पहुंचा। अल्काराज ने पांचवें सेट के पहले गेम में अपनी सर्विस गंवा दी। इस सेट के छठे गेम में रोमांच तब चरम पर पहुंच गया जब अल्काराज ने ड्रॉप शॉट को लेने के लिए दौड़ लगाई और पूरी गति से स्लाइड करते हुए फोरहैंड विनर शॉट लगाया। इससे दर्शक खुशी से झूम उठे। अल्काराज ने आखिर में पांचवें सेट में 5-4 पर ज़्वेरेव की सर्विस तोड़ी और फिर पहले मैच प्वाइंट को भुनाकर फाइनल में प्रवेश किया।

भारत की ईशारानी बरुआ थाईलैंड मास्टर्स के क्वार्टरफाइनल में पहुंची

पटुमवान (थाईलैंड) (एजेंसी) । भारत की ईशारानी बरुआ ने चीनी ताइपे की शटलर सुंग को हराकर थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। बैडमिंटन रैंकिंग में 48वें स्थान पर काबिज 22 वर्षीय भारतीय शटलर ने गुरुवार को खेले गये मुकाबले में 34वें स्थान पर काबिज ताइपे की प्रतिद्वंद्वी सुंग को 21-13, 14-21, 21-14 से हराकर बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 टूर्नामेंट में अगले दौर में जगह बनाई। पहला गेम बेहद करीबी रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ी 11-11 के स्कोर पर बराबरी पर थे, जिसके बाद भारतीय शटलर ने 14-13 की बढ़त बना ली। इसके बाद ईशारानी ने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए लगातार सात अंक जीतकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में सुंग ने वापसी का प्रयास किया, जो एक बार फिर 13-13 के स्कोर तक बराबरी पर रहा। इस बार, ताइपे की शटलर ने शानदार वापसी करते हुए अगले आठ में से सात अंक जीतकर गेम को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। हालांकि, तीसरा गेम पूरी तरह से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम रहा, जो इससे पहले 2023 गुवाहाटी मास्टर्स में सुंग से हार गई थी। इससे पहले दोनों के बीच केवल एक ही मुकाबला हुआ था। महिला एकल के एक अन्य मुकाबले में देविका सिहाग ने दूसरे राउंड में चीनी ताइपे की तुंग सिउ-टोंग को 32 मिनट तक चले मुकाबले में 21-14, 21-14 से हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। 51वीं रैंकिंग पर काबिज अनमोल खरब को महिला एकल मुकाबले में हुआंग यू-सुन से 10-21, 21-19, 21-19 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, महिला एकल खिलाड़ी श्रीयांशी वालीशेट्टी को करुपथेवन लेटशाना ने 17-21, 22-20, 19-21 से हराया।

आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया पीसीबी का मजाक, हम विश्वकप में उसके जगह लेने तैयार

नई दिल्ली । टी20 विश्वकप क्रिकेट में भाग लेने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक फैसला नहीं किया है हालांकि उसने अपनी टीम घोषित कर दी है। पीसीबी ने कहा था कि वह इस टूर्नामेंट से बाहर भी रह सकता है। इसी को लेकर अब आइसलैंड क्रिकेट ने पीसीबी पर व्यंग्य कसा है। आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो वे उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसमें ये भी कहा है कि अगर 2 फरवरी तक फैसला हो जाए तो वे तत्काल ही श्रीलंका पहुंच सकते हैं। पाक को चिढ़ाते हुए आइसलैंड क्रिकेट ने केफ्लाविक से कोलंबो तक की यात्रा योजनाओं का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। साथ ही इस पोस्ट में आखिरी समय पर बुलाए जाने पर आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को भी मजाकिया अंदाज में दिखाया गया। यहां तक कि उन्होंने अपने ओपनिंग बल्लेबाज की 卐अनिद्रा卐 का भी जिक्र कर दिया, जिसने प्रशंसकों को पीसीबी पर हंसने का अवसर जरुर मिल गया है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बांग्लादेश के विश्वकप से नाम वापस लेने पर उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल किया था। तब पीबीबी ने बांग्लादेश बोर्ड का समर्थन करते हुए कहा कि वह भी विश्वकप से बाहर रह सकता है।

मनप्रीत सिंह समेत तीन प्लेयर्स पर बड़ी कार्रवाई, प्रो लीग के संभावित खिलाड़ियों की सूची से किया बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय पुरूष हॉकी टीम के अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह समेत तीन खिलाड़ियों को प्रो लीग के आगामी सत्र से पहले संभावित खिलाड़ियों की सूची से बाहर के फैसला पर भले ही कइयों को हैरानी हुई हो लेकिन सूत्रों के अनुसार यह फैसला पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ही 'अनुशासनात्मक' कारणों से ले लिया गया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी भारतीय खिलाड़ी के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों का हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की के (412) रिकॉर्ड की बराबरी से रोकने के लिए मनप्रीत को बाहर किया गया है।

मनप्रीत इस रिकॉर्ड से एक मैच दूर हैं। टीम के करीबी सूत्रों ने हालांकि बताया कि मनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और गोलकीपर कृशन बहादुर पाठक को बाहर करने का फैसला पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ही ले लिया गया था। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में सात से दस दिसंबर 2025 के बीच दो टेस्ट और एक नुमाइशी मैच खेले थे। सूत्रों ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अनुशासनहीनता का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया था जब एक खिलाड़ी टीम बैठक से गायब था और बाद में पता चला कि उसे मनप्रीत, दिलप्रीत और पाठक ने कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ वाली च्युइंग गम खिलाई थी जिससे वह बेहोश हो गया और पूरी रात उसे संभालना पड़ा। अगली सुबह वह टीम बैठक में भी नहीं जा सका।'

उन्होंने आगे कहा, 'खिलाड़ियों ने अपने साथी खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ खिलाने के लिए बाद में माफी मांगी लेकिन टीम बैठक में तब ही उन्हें आगामी शिविर से बाहर रखने का फैसला सुना दिया गया था।' यह भी पता चला है कि कोच क्रेग फुल्टोन की ओर से घटना की कोई लिखित रिपोर्ट हॉकी इंडिया को नहीं दी गई है। राउरकेला में अगले महीने होने वाले प्रो लीग के आगामी सत्र के लिए हॉकी इंडिया ने गुरुवार को संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की जिसमें कोच ने कहा कि कार्यभार प्रबंधन के लिये कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।

राउरकेला में 10 से 15 फरवरी तक होने वाले FIH प्रो लीग मैचों से पहले एक से सात फरवरी तक यह शिविर आयोजित किया जाएगा। मनप्रीत की सह कप्तानी में रांची रॉयल्स टीम हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में पहुंची थी और टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन भी काबिले तारीफ रहा जिससे उन्हें बाहर किए जाने को लेकर सवाल उठने लाजमी हैं। वहीं कृशन और दिलप्रीत ॥द्धरु जीतने वाली कलिंगा लांसर्स टीम का हिस्सा थे। दो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीमों के सदस्य और 33 वर्षीय पूर्व भारतीय कप्तान मनप्रीत 15 वर्षों में पहली बार शिविर के लिए संभावित खिलाड़ियों की सूची में जगह नहीं बना पाए हैं।

पीटी उषा के पति वी. श्रीनिवासन का निधन

नई दिल्ली । भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा के पति वी. श्रीनिवासन का आज सुबह निधन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीनिवासन आज सुबह अपने आवास पर अचानक ही बेहोश हो गये। उन्हें तत्काल करीब के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री, खेलमंत्री के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारियों और खिलाड़ियों ने भी श्रीनिवासन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख की इस घड़ी में उषा से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। प्रधानमंत्री ने इस अपूरणीय क्षति पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को धैर्य और शक्ति देने की कामना की। गौरतलब है कि 67 साल के श्रीनिवासन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ) में उप अधीक्षक रहे थे। इस दंपति का एक बेटा है, जिसका नाम उज्ज्वल है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी श्रीनिवासन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने उषा और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही ईश्वर से इस कठिन समय को सहने की शक्ति परिवार देने की प्रार्थना की है। उषा दिग्गज एथलीट रही है। एशियाई खेलों सहित कई अन्य स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

चीन ने जापान से वापस मंगा लिया आखिरी पांडा जोड़ा

बीजिंग, एजेंसी। तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन ने जापान से पांडा के आखिरी जोड़े को वापस मंगवा लिया है। करीब 50 वर्षों में पहली बार जापान पांडा विहीन हो गया है। चीन ने संबंधों को सामान्य करने के उद्देश्य से 1972 में अपने पड़ोसी जापान को पहली बार पांडा भेंट किया था। चीन अक्सर पांडों का कूटनीतिक इस्तेमाल करता है। चीन व जापान के बीच आपसी बातचीत के आधार पर पांडों की वापसी फरवरी में तय थी। लेकिन, चीन ने बुधवार को ही पांडा शियाओ व लेई को वापस मंगवा लिया।

उत्तर कोरिया मजबूत करेगा परमाणु प्रतिरोधक क्षमता

प्योंगयाग, एजेंसी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की योजना का संकेत दिया है। जोंग ने एक बयान में कहा कि आगामी सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में देश के परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत करने की योजनाओं का खुलासा किया जाएगा। सरकारी मीडिया के अनुसार, उत्तर कोरिया ने उन्नत बड़े-कैलिबर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का लाइव-फायर अभ्यास किया, जिससे उसकी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।

द. कोरिया- पूर्व प्रथम महिला कियॉन को 20 माह जेल की सजा

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरियाई अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रथम महिला किम कियॉन ही को भ्रष्टाचार के मामले में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई। कियॉन पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी हैं। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किम को यूनिफिकेशन चर्च से व्यापारिक सुविधाओं के बदले रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराया और 20 महीने की जेल की सजा सुनाई।

धमाके के साथ जाफर एक्सप्रेस बेपटरी हुई बलोचों ने ली जिम्मेदारी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। संबंधित रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को धमाका अबाद स्टेशन पर हुआ। इसकी जिम्मेदारी बलोच सशस्त्र समूह ने ली है। मालूम हो कि इससे पहले भी बीते साल मार्च में बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाइजैक कर लिया था। इसमें 21 बंदियों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि, सेना ने बाद में ट्रेन को छुड़ा लिया था और 33 विद्रोहियों को मारने का दावा किया था।

बिना लैंडिंग गियर के उतरा नासा का विमान, निकलीं लपटें, टला हादसा

वाशिंगटन, एजेंसी। नासा का एक खोजी विमान हवा में ही खराब हो गया और बिना लैंडिंग गियर के उसे टेक्सास हवाईअड्डे पर उतरना पड़ा। विमान रनवे पर पेट के बल रगड़ खा रहा था और पीछे आग की लपटें निकल रही थीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा बच गया। नासा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चालक दल सुरक्षित हैं।

नेपाल में नकली भारतीय मुद्रा के साथ बिहार के दो युवक गिरफ्तार

रौतहट, एजेंसी। नेपाल के रौतहट जिले में नेपाली सुरक्षा बलों ने बिहार के दो निवासियों को नकली भारतीय नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के प्रवक्ता मनीष थापा के अनुसार, सीतामढ़ी जिले के बिक्रम कुमार पासवान और राहेश कुमार साह को मंगलवार रात पकड़ा गया। दोनों भारतीय पंजीकरण वाली मोटरसाइकिल से नेपाल में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय नियमित सुरक्षा जांच के दौरान उनके पास से 2500 रुपये की जाली मुद्रा बरामद हुई। इसमें एक 500 रुपये का नोट और दस 200 रुपये के नोट शामिल थे। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपियों को जिला पुलिस कार्यालय, रौतहट को सौंप दिया गया है।

न्यूयॉर्क में बिखरी भारतीय संस्कृति-पर्यटन की छटा

न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क में आयोजित प्रमुख प्रदर्शनी में भारत के पर्यटन व सांस्कृतिक स्थलों की छटा बिखरी। प्रदर्शनी के जरिये हजारों आगंतुकों को देश की समृद्ध विरासत व पाक कला के बारे में जानने का अवसर मिला। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने जैकब जेविट्स सेंटर में आयोजित ट्रैवल एंड एडवेंचर शो 2026 में भाग लिया। यहां 10 हजार से अधिक आगंतुकों ने भारत के पर्यटन व सांस्कृतिक परिदृश्य की झलक देखी। इस वर्ष भारत मंडप विशाल कन्वेंशन सेंटर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही तैयार किया गया। भारतीय महावाणिज्य दूतावास के कांसुल जनरल बिनय प्रधान ने 24-25 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में भारत मंडप का उद्घाटन किया। भारत मंडप में विशेष रूप से भारत की टूर एवं ट्रैवल कंपनियों ने भाग लिया और अपनी योजनाएं प्रदर्शित कीं।

बांग्लादेश चुनाव को लेकर यूनुस सरकार पर भड़कीं शेख हसीना

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की अपदस्थ नेता शेख हसीना ने भारत में निर्वासन में रहते हुए अपने देश के आगामी चुनावों की कड़ी आलोचना की है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि उनकी पार्टी को चुनावों में भाग लेने से रोक दिया गया है। उनके ये बयान अगले महीने होने वाले महत्वपूर्ण मतदान से पहले तनाव को और गहरा कर सकते हैं। हसीना, जिन्हें 2024 में छात्र विद्रोह को दबाने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जिसके कारण उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया था। उन्होंने पिछले सप्ताह एसोसिएटेड प्रेस को एक ईमेल में चेतावनी दी थी कि समावेशी और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के बिना बांग्लादेश को लंबे समय तक अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा।

अंतरिम सरकार ने जानकर उनकी पार्टी को चुनाव से दूर कर रही : उन्होंने यह भी दावा किया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जानबूझकर उनकी पार्टी - पूर्व सत्तारूढ़ अवामी लीग को चुनाव से बाहर कर रही है। वहीं, उनके लाखों समर्थकों को मताधिकार से वंचित कर दिया। उन्होंने लिखा, 'जब भी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जाता है, तो इससे असंतोष गहराता है, संस्थानों की वैधता कम होती है और भविष्य में अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है।' हसीना ने आगे कहा बहिष्कार पर आधारित सरकार विभाजित राष्ट्र को एकजुट नहीं कर सकती, '

एक तनावपूर्ण चुनाव : बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में 127 मिलियन से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं, जिसे व्यापक रूप से दशकों में देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव और जन विद्रोह के बाद हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद पहला चुनाव माना जा रहा है। युनुस की अंतरिम सरकार इस प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। इसके साथ ही मतदाता व्यापक राजनीतिक सुधारों पर प्रस्तावित संवैधानिक जनमत संग्रह पर भी विचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार पिछले सप्ताह राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर रैलियों के साथ शुरू हुआ।

निष्पक्ष चुनाव का वादा : हसीना के हफ्तों तक चले हिंसक अशांति के बाद 5 अगस्त, 2024 को भारत भाग जाने के तीन दिन बाद यूनुस बांग्लादेश लौट आए और सत्ता

संभाली। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का वादा किया है, लेकिन आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक मानकों को पूरा करेगी और हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद क्या यह वास्तव में समावेशी होगी। जनमत संग्रह को लेकर सुरक्षा और अनिश्चितता को लेकर भी चिंताएं हैं, जिससे संविधान में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

युनुस के कार्यालय ने एपी को दिए एक बयान में कहा कि सुरक्षा बल सुचारू रूप से चुनाव सुनिश्चित करेंगे और किसी को भी जबरदस्ती या हिंसा के माध्यम से परिणाम को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देंगे। बयान में आगे कहा गया है कि प्रक्रिया की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मानवाधिकार समूहों को आमंत्रित किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि यूरोपीय संघ और राष्ट्रमंडल सहित लगभग 500 विदेशी पर्यवेक्षकों के 12 फरवरी को होने वाले चुनावों का अवलोकन करने की उम्मीद है।

भविष्य को लेकर चिंताएं : हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद से बांग्लादेश को कई राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मानवाधिकार और अल्पसंख्यक समूहों ने अंतरिम अधिकारियों पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। हसीना की पार्टी ने अपने सदस्यों की मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत में मौत का आरोप लगाया है, जिसे सरकार ने नकार दिया है। आलोचकों ने इस्लामी समूहों के बढ़ते प्रभाव और अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर होने वाले हमलों पर भी चिंता व्यक्त की है। यूनुस के शासनकाल में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, कई पत्रकारों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। देश के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के कार्यालयों पर आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है।

इस बीच, 60 वर्षीय तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी चुनाव में अग्रणी दावेदार के रूप में उभरी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (जिनका पिछले महीने निधन हो गया) के पुत्र रहमान, जो हसीना की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थीं। 17 वर्षों से अधिक के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद दिसंबर में घर लौटे। उन्होंने 17 करोड़ लोगों के इस दक्षिण एशियाई राष्ट्र की स्थिरता के लिए काम करने का वादा किया है। फरवरी में होने वाले चुनाव में रहमान का मुख्य प्रतिद्वंद्वी 11 सहयोगी समूहों का गठबंधन है, जिसका नेतृत्व एक इस्लामी पार्टी, जमात-ए-इस्लामी कर रही है। हसीना के शासनकाल में जमात-ए-इस्लामी पर भारी दबाव था। उसे चुनावों में भाग लेने से रोक दिया गया था। बांग्लादेश के पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित युद्ध अपराधों के आरोपों में इसके शीर्ष नेताओं को फांसी या कारावास की सजा का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ने 2014 और 2024 के चुनावों का बहिष्कार किया था। इसने 2018 में चुनाव में भाग लिया था, लेकिन बाद में हसीना पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था।

हसीना का कहना है कि देश को अपने घावों को भरना होगा : आलोचकों ने लंबे समय से हसीना पर तेजी से सत्तावादी व्यवस्था चलाने का आरोप लगाया है। असहमति और अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन को लेकर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, और उनकी सरकार के अधीन सुरक्षा एजेंसियों पर जबरन गायब किए जाने के आरोप लगे हैं। फिर भी, हसीना ने बांग्लादेश की उस अदालत को 'कंगारू अदालत' करार दिया है जिसने विद्रोह के दौरान हुई हत्याओं के सिलसिले में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने मुकदमे की निष्पक्षता पर चिंता जताई है। एपी को भेजे गए अपने ईमेल में हसीना ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए बांग्लादेश को राजनीतिक प्रतिबंधों और बहिष्कार के चक्र को तोड़ना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी सरकार के तहत कुछ चुनाव 'वास्तव में सहभागी नहीं थे क्योंकि प्रमुख राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बहिष्कार करना चुना।' उन्होंने कहा, 'मैं मानती हूं कि यह आदर्श स्थिति से बहुत दूर था,' और साथ ही यह भी कहा कि बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों को अब इस चक्र को तोड़ना होगा। 'अन्यथा, कोई सुधार नहीं होगा।' उन्होंने आगे कहा कि देश को एक ऐसी वैध सरकार की जरूरत है जो लोगों की वास्तविक सहमति से शासन करे। उन्होंने कहा, 'देश के घावों को भरने का यही सबसे अच्छा तरीका है।'

ट्रम्प का हाथ थामकर मंच पर पहुंची अमेरिकी रैपर निकी मिनाज

कहा- राष्ट्रपति की फैन हूं; ट्रम्प बोले- निकी के नाखून काफी खूबसूरत

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका की हिप-हॉप सिंगर और रैपर निकी मिनाज ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हाथ मिलाया और खुद को राष्ट्रपति का सबसे बड़ा प्रशंसक बताया। निकी मिनाज ने मंच पर ट्रम्प के साथ हाथ जोड़ते हुए दर्शकों से कहा, 'मैं शायद राष्ट्रपति की नंबर 1 फैन हूं, और यह बात नहीं बदलेगी।' मिनाज ने कहा कि आलोचकों की आलोचना और नफरत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह उनकी समर्थन को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा, 'लोग जो कहते हैं, वह मुझे प्रभावित नहीं करता। यह मुझे राष्ट्रपति का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। यह हमें सभी को और अधिक समर्थन करने के लिए प्रेरित करेगा।'

निकी ने ट्रम्प के विरोधियों पर आरोप लगाया कि वे राष्ट्रपति को अनुचित तरीके से निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम उन्हें राष्ट्रपति को बुली करने नहीं देंगे। उनके पीछे बहुत ताकत है और भगवान उनकी रक्षा

कर रहे हैं।' कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने निकी मिनाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने उन्हें इतिहास की सबसे महान और सफल महिला रैपर बताया और 'ट्रम्प अकाउंट्स' में सैकड़ों हजारों डॉलर के दान के लिए धन्यवाद दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, निकी ने 1.5 लाख से 3 लाख डॉलर तक का योगदान दिया है, हालांकि सटीक राशि की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रम्प ने मजाक में कहा कि निकी के लंबे नाखून खूबसूरत हैं इससे प्रभावित होकर वे भी अपने नाखून बढ़ाएंगे।

नॉर्थ कोलंबिया के ग्रामीण इलाके में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी 15 लोगों की मौत

बोगोटा, एजेंसी। नॉर्थ कोलंबिया के नॉर्ट डी सेंटेंडर प्रांत के एक ग्रामीण इलाके में बुधवार को एक छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। सरकारी एयरलाइन कंपनी सतेना इस फ्लाइट का संचालन करती थी। कंपनी ने कहा कि घटनास्थल पर एक बचाव दल भेजा गया। विमान एचके4709 स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:42 बजे राजधानी कुकुटा के हवाई अड्डे से ओकाना के लिए रवाना हुआ था। ओकाना पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह उड़ान आमतौर पर लगभग 40 मिनट की होती है। सतेना के बयान के अनुसार, विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद हुआ। एयरलाइन ने कहा कि छोटे विमान में दो चालक दल के

सदस्य और 13 यात्री सवार थे।

विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स के नाम : यात्रियों में - मारिया अल्वारेज बारबोसा, कार्लोस साल्सेडो, रोलैंडो पेनालोजा ग्वाल्ड्रोन, मारिया डियाज रोड्रिगेज, मायरा एवेंडानो रिनकॉन, अनायेसेल क्विंटेरो, करें पैरालेस वेरा, एनिरली जूलियो ओसोरियो, गिनेथ रिनकॉन, डायोजनीज क्विंटेरो अमाया, नतालिया अकोस्टा साल्सेडो, माइरा सांचेज क्रिएडो, जुआन पाचेको मेजिया

क्रू मेंबर्स में - कैप्टन मिगुएल वेनेगास, कैप्टन जोस डे ला वेगा

उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ही एटीसी से टूटा संपर्क : जानकारी के मुताबिक, विमान ने सुबह 11:42 बजे कुकूता शहर के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उसे ओकान्या शहर जाना था, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। आमतौर पर यह सफर करीब 40 मिनट में पूरा हो जाता है। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इस घटना के दौरान विमान में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें दो क्रू मेंबर और13 यात्री शामिल थे।

विमान हादसे के कारणों की जांच जारी : इन यात्रियों में एक प्रमुख नाम डायोजेनेस क्विंटेरो का भी था, जो अपने इलाके में आंतरिक सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी मौत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी दुख और चिंता है। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर एचके4709 बताया गया है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसा किन कारणों से हुआ। जांच एजेंसियां इसकी जांच करेंगी कि तकनीकी खराबी थी, मौसम की वजह से हुआ या कोई और कारण था।

भारत और यूरोपीय संघ के समझौते को ट्रंप के मंत्री ने बताया बेहद निराशाजनक

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए नए व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यूरोप ने यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा और चिंता को छोड़कर व्यापारिक मुनाफे को ज्यादा महत्व दिया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में बेसेंट ने यूरोपीय संघ के इस रुख पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध के बावजूद यूरोप ने अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है।

व्यापार समझौते से क्या होगा फायदा? : अमेरिका का यह बयान यूरोपीय संघ और भारत के बीच लंबे

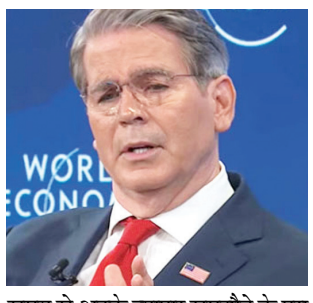

समय से अटके व्यापार समझौते के पूरा होने के ठीक एक दिन बाद आया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आपसी व्यापार को बढ़ाना और अमेरिका पर यूरोप की निर्भरता को कम करना है। इस डील के तहत 96.6 प्रतिशत व्यापारिक सामानों पर आयात शुल्क या तो खत्म कर दिया जाएगा या काफी कम होगा। जानकारों का मानना है कि इस कदम से 2032 तक भारत को होने वाला यूरोपीय निर्यात दोगुना हो जाएगा। इससे यूरोपीय कंपनियों को करीब चार अरब यूरो की बड़ी बचत होने की उम्मीद है।

बेसेंट ने लगाया आरोप : बेसेंट ने कहा कि इस समझौते से अब यह साफ हो गया है कि यूरोपीय संघ ने पिछले साल भारत पर ऊंचे टैक्स लगाने के अमेरिकी फैसले का समर्थन क्यों नहीं किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश असल में रूस के युद्ध को पैसा पहुंचा रहे हैं। उनके मुताबिक, रूस का कच्चा तेल भारत जाता है और वहां से रिफाइंड तेल उत्पाद यूरोप में जाते हैं। इस तरह यूरोप अनजाने में अपने ही खिलाफ युद्ध के लिए रूस की मदद कर रहा है।

कहा- अमेरिका ने यूरोप की तुलना दिए कहीं अधिक बलिदान : अमेरिकी वित्त मंत्री ने बताया कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। लेकिन यूरोपीय देशों ने इसके उलट भारत के साथ व्यापारिक डील कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए यूरोप के मुकाबले कहीं ज्यादा कोशिशें की हैं। बेसेंट के अनुसार, इस संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की तुलना में कहीं अधिक बलिदान दिए हैं।

अल्बानिया- भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनीं एआई मंत्री पर शक

तिराना, एजेंसी। अल्बानिया ने साल 2025 में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मंत्री 'डिएला' बनाया था, जिसका मकसद देश में फैली भ्रष्टाचार को कम करना था। हालांकि अब एक बड़ा विवाद सामने आया है डिएला को बनाने वाली नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी के दो प्रमुख अधिकारी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए हैं।

नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी की डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्हें ठेकों में धमकी देकर हेरफेर करने, रिश्वत लेने और क्रिमिनल संगठन से जुड़े होने का आरोप है। यह वही एजेंसी है जो सरकार की डिजिटल व्यवस्था संभालती है। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक इन अधिकारियों पर औपचारिक रूप से कोई आरोप तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री रामा ने कहा कि वे जांच पूरी होने तक कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अल्बानिया यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी शर्त है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सवाल उठने लगे है कि क्या एआई को कुछ सबूत छिपाने या हेरफेर करने के लिए डिएला को प्रोग्राम किया जा सकता है।

डिएला बोलीं- मैं इंसान नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं : डिएला एक वर्चुअल अवतार है, जो पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में दिखाई देती है। पिछले साल से डिएला कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में बोल चुकी है और दुनिया भर में एआई को सरकारी कामों में इस्तेमाल करने के लिए

प्रोत्साहित कर रही है। सितंबर में अल्बानिया की संसद में वीडियो के जरिए डिएला ने कहा था कि वह इंसान नहीं है, इसलिए उसके पास कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या स्वार्थ नहीं है। सिर्फ डेटा, ज्ञान और एल्गोरिदम हैं, जो नागरिकों की निष्पक्ष सेवा के लिए समर्पित हैं। उसने कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर उसे दुख हुआ है।

सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों की मदद करती है वर्चुअल अवतार डिएला : डिएला नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाएं दिलाने में मदद करती है, जैसे दस्तावेज जारी करना या अपॉइंटमेंट बुक करना। इससे पहले अधिकारियों को रिश्वत देकर काम करवाना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म हो रही है।

जल्द ही डिएला सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के आवेदनों की जांच करेगी और डेटा के आधार पर तय करेगी कि कौन सा बोलीदाता सबसे योग्य है। इसका काम ऑडिट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री रामा ने इसे दीएला (रोशनी) नाम दिया है, ताकि सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता आए।

ब्रिटिश पीएम 8 साल बाद चीन पहुंचे: कोरोनाकाल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था

बीजिंग, एजेंसी। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर बुधवार को 8 साल बाद तीन दिन के दौरे पर चीन पहुंचे। इससे पहले 2018 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे चीन पहुंची थी। पिछले 8 सालों में ग्लोबल राजनीति काफी बदल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रमक नीतियों और बयानों की वजह से यूरोपीय देश नए पार्टनर तलाश रहे हैं, ऐसे में चीन उन्हें एक मजबूत विकल्प नजर आ रहा है। चीन रवाना होने से पहले स्टार्मर ने मीडिया से कहा था कि ब्रिटेन को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन चीन को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा।

वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी। ब्रिटेन भले ही आज चीन को जरूरी देश बता रहा है, लेकिन 2020 में कोरोना के वक्त ही उसने चीनी

टेक कंपनी हुआवे को जासूसी के शक में अपने देश से निकाल दिया था।

ब्रिटेन ने चीनी कंपनी को 5जी प्रोजेक्ट से निकाला था : ब्रिटिश सरकार ने 2010 में चीनी कंपनी हुआवे को देश में मोबाइल नेटवर्क पर काम करने की इजाजत दी। उसी समय हुआवे के ऑफिस में 'द सेल' नाम का एक खास दफ्तर बनाया गया, जिसके जरिए सरकार कंपनी के काम पर नजर रखती थी। इसे कई सालों तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम माना गया।

इस दफ्तर में ब्रिटेन के साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स काम करते थे। हुआवे के खर्च पर वे उसके हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करते थे, ताकि कोई ऐसा कोड न हो जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। फिर भी ब्रिटेन की सरकार को इस सिस्टम से पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। करीब 10 साल तक हुआवे को काम करने देने के बाद, सरकार ने साल 2020 में फैसला किया कि उसे ब्रिटेन के 5जी नेटवर्क से बाहर कर दिया जाएगा। उसी साल संसद की एक जांच में कहा गया कि हुआवे और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच मिलीभगत के साफ सबूत हैं। जो 5 जी इक्विपमेंट पहले से लगे हैं, उन्हें हटाना होगा।

अब 'द सेल' इस बात की मिसाल बन गया है कि चीन के साथ रिश्तों में ब्रिटेन को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। एक तरफ खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां सस्ती तकनीक चाहती हैं और सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स और पूर्व डिप्लोमेट्स का कहना है कि अलग-अलग सरकारें चीन को लेकर सही संतुलन नहीं बना पाई हैं। इसकी वजह से ब्रिटेन की पॉलिसी में शक और डर नजर आता है।

एक्सपर्ट्स बोले- चीनी ऐसी हकीकत जिसका सामना करना जरूरी : स्टार्मर की ये यात्रा चीन को लेकर बने शक और डर को कम करने की कोशिश है। ये विजिट ऐसे समय हो रही है जब यूरोप और चीन के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हैं। हाल के हफ्तों में फिनलैंड और आयरलैंड के प्रधानमंत्री भी चीन जा चुके हैं। जर्मन चांसलर के भी फरवरी में चीन जाने की संभावना है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और यूरोपियन यूनियन पार्टनर हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं और सहयोग मतभेदों से ज्यादा अहम है।

पीएम कीर स्टार्मर ने भी माना है कि चीन को लेकर ब्रिटेन का रवैया कभी बहुत नरम रहा, तो कभी बहुत सख्त। उनका कहना है कि वे चीन के साथ 'गोल्डन एरा' या 'आइस एज' जैसी दो टूक सोच में भरोसा नहीं करते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रिटेन अब चीन को न तो दोस्त मान रहा है और न दुश्मन, बल्कि एक ऐसी हकीकत मान रहा है जिसका सामना करना जरूरी है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली में राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी.... मांगी जा रही ये सारी जानकारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उन राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी किया है जिनके पास जमीन के साथ घर और अपनी गाड़ी भी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी जांच अभियान के बाद इसतरह के लोगों को मैसेज के जरिए नोटिस जारी किया जा रहा है। उनसे जवाब देने को कहा गया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तब उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ने सरकार के इस तरह जारी नोटिस पर सवाल उठाकर सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी है। रेखा सरकार की तरफ से जारी नोटिस में उनकी गाड़ी, घर की जानकारी के साथ ही उनके आय के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। साथ ही राशन कार्ड के लिए न्यूनतम सालाना एक लाख की आय को लेकर राजस्व विभाग की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र भी जमा करने को कहा गया है। यह आय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं,तब उनका अगले महीने से राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। दिल्ली में बीते दिनों राशन कार्ड धारकों को लेकर चले जांच अभियान के दौरान आठ लाख से अधिक लोग अपात्र मिले हैं। राशन डीलर संघ के मुताबिक दिल्ली सरकार का यह जांच अभियान ठीक है लेकिन इसतरह के लोगों को नोटिस दिया जा रहा है जिनका दिल्ली में कोई जमीन नहीं है। उनके मुताबिक दिल्ली में बहुत से लोग बाहर से आकर रहते हैं। उनकी गांव में थोड़ी बहुत जमीन है। इस बात को आधार बनाकर उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है।

क्रिप्टो निवेश के नाम पर 1.80 करोड़ की ठगी, 26 लोगों को बनाया शिकार

जोधपुर (एजेंसी)। राजस्थान के जोधपुर जिले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर बड़े स्तर की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मोटे मुनाफे का लालच देकर 26 लोगों से करीब 1.80 करोड़ रुपए हड़प लिए और बाद में ऑफिस बंद कर फरार हो गए। इस संबंध में जोधपुर के थाने में न्यायालय परिवाद के जरिए मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित सिद्रपा भीमराय पडशेटी, निवासी सालोटगी, जिला बीजापुर (कर्नाटक) ने रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2022 में उन्होंने यूट्यूब पर 'केपमोर अपेक्स' नामक कंपनी का वीडियो विज्ञापन देखा था। इसमें अजय आर्य नामक व्यक्ति क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का दावा कर रहा था और ट्रेडिंग ट्रेनिंग देने की बात वीडियो में की जा रही थी। विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी अजय ने खुद को श्रीगंगानगर निवासी बताकर देश के कई शहरों में कंपनी के ऑफिस होने का दावा किया। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि निवेश करने वालों को तय समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके झांसे में आकर पीड़ित और उसके परिचितों ने करीब सवा साल के दौरान नकद और ऑनलाइन माध्यम से बड़ी रकम निवेश कर दी। बाद में अजय और उसके साथियों ने कर्नाटक के विजयापुरा में खोला गया ऑफिस बंद कर श्रीगंगानगर आ गए। पीड़ित का आरोप है कि बार-बार संपर्क करने पर आरोपी केवल बहाने बनाते रहे और रुपए लौटाने का झूठा आश्वासन देते रहे। कुछ समय बाद अजय घर से गायब हो गया और उसका मोबाइल भी बंद आने लगा। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इसी तरह कई अन्य लोगों से भी करोड़ों की ठगी की और ठगी की रकम से अपने व परिवार के नाम संपत्तियां खरीदीं। रिपोर्ट के आधार पर अजय आर्य, दीपक आर्य, लजपत आर्य, सौरभ चावला, सलोनी चावला, करमजीत सिंह, बलजीत सिंह और राजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

लखनऊ एयरपोर्ट से सऊदी के लिए उड़ा विमान...फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट से सऊदी अरब जा रहे एक विमान की शुक्रवार को इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उड़ान के कुछ समय बाद विमान में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। सूत्रों के मुताबिक, जब विमान मुंबई के पास पहुंचा, तब केबिन प्रेशर में समस्या आ गई। इसके चलते कुछ यात्रियों को सांस लेने में परेशानी हुई। गंभीर हालात देखकर पायलट ने पहले मुंबई एयरपोर्ट से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन वहां से परमिशन नहीं मिली। इसके बाद पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट से संपर्क किया। लखनऊ से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिलते ही विमान वापस लौट आया। करीब 82 मिनट में विमान सुरक्षित रूप से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। खराबी दूर होने पर विमान जेद्दा के लिए रवाना हो गया। यह विमान सऊदिया अरबिया एयरलाइंस का था। फ्लाइट नंबर एसवी-891 जेद्दा जा रही थी। विमान में 275 यात्री, 4 पायलट और 6 क्रू मेंबर सवार हैं। जानकारी के मुताबिक, विमान का तय समय दोपहर 12:05 बजे था, लेकिन यह 12:23 बजे उड़ान भर सका। दोपहर करीब 1:45 बजे विमान को बीच रास्ते से वापस लाना पड़ा। यात्रियों को विमान से उतारा नहीं गया। इंजीनियरों ने तकनीकी खराबी दूर कर दी। विमान शाम 4:20 बजे जेद्दा के लिए रवाना हुआ।

क्या है केबिन प्रेशर- विमान में केबिन प्रेशर आर्टिफिशियल एयर प्रेशर है, जिसे हवाई जहाज के अंदर बनाए रखा जाता है। इससे जब विमान 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तब भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। केबिन प्रेशर उस ऊंचाई में भी 6,000-8,000 फीट की ऊंचाई के बराबर वाला एयर प्रेशर बनाकर रखता है। इससे यात्री आसानी से सांस लेते रहते हैं।

भारत में निपाह वायरस के फैलने का जोखिम कम... डब्ल्यूएचओ ने माना

नई दिल्ली (एजेंसी)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि भारत में निपाह वायरस के फैलने का जोखिम कम है और देश में वायरस संक्रमण के दो मामले सामने आने के बाद यात्रा या व्यापार प्रतिबंध लगाने की कोई जरुरत नहीं है। यह घटना कई एशियाई देशों द्वारा अपने क्षेत्रों में आने वाले लोगों में वायरस के लक्षणों की जांच तेज करने के बाद हुई है। चूंकि भारत पहले भी निपाह के प्रकोप को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता दिखा चुका है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मान लिया है कि मानव-से-मानव संक्रमण में वृद्धि का कोई प्रमाण नहीं है।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अन्य भारतीय राज्यों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके फैलने की संभावना कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि पिछले साल दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस रोग के केवल दो मामले सामने आए हैं। इसके बाद, केंद्र ने बंगाल सरकार के समन्वय से प्रोटोकॉल के अनुसार त्वरित और व्यापक जन स्वास्थ्य उपाय शुरू किए। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और प्रकोप से निपटने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए है।

सच्चा न्याय वही है जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो: अखिलेश

-यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष एक राय नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशंस 2026 के प्रावधान प्रथम दृष्टया अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सत्ताधारी बीजेपी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे संविधान, सामाजिक समरसता और सनातन मूल्यों की रक्षा से जुड़ा अहम कदम बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण इसका उदाहरण है। वहीं निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो संविधान के अनुरूप है।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्र और नेता बृजभूषण शरण सिंह ने फैसले को न्यायसंगत बताते हुए कहा कि नए नियमों से सामाजिक टकराव की आशंका थी, जिसे कोर्ट ने समय रहते रोक लगा दी है।

वहीं, विपक्षी दलों की राय इस मुद्दे पर बंटी हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अखिलेश ने कहा कि सच्चा न्याय वही है जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो और कानून की भाषा व नीयत दोनों साफ हों। मायावती ने कहा कि नए नियमों से सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था, इसलिए कोर्ट का फैसला सही है।

इसके उलट कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जाति और धर्म के नाम पर विवाद खड़ा कर रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे 'यथास्थिति बनाए रखने' की कोशिश बताया। इस बीच कुमार विश्वास ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश इस समय किसी भी तरह के बंटवारे को सहन नहीं कर सकता और सरकार को समाधान की दिशा में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

माघ मेला छोड़कर गए शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन

-अविमुक्तेश्वरानंद ने रखी दो शर्त, दो बड़े अधिकारी संगम में करवाएंगे स्नान

वाराणसी (एजेंसी)। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने बताया किया योगी सरकार ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे, प्रयागराज के अफसरों को यह उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे माघ पूर्णिमा एक फरवरी के स्नान के बाद शंकराचार्य जाएंगे तब तक उनको मना लेंगे। 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी आने के बाद लखनऊ के दो बड़े अधिकारियों ने सरस्वती से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में स-सम्मान स्नान कराने की बात कही है। इस पर शंकराचार्य ने दो शर्त रखी हैं। पहली- जिम्मेदार माफी मांगे, लिखित माफीनामा दें वहीं दूसरी- चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने बताया कि शासन के कुछ अधिकारी वाराणसी आएंगे। शंकराचार्य को प्रयागराज लेकर जाएंगे। उन्हें माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कराएंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा मौनी अमावस्या से उनके साथ हैं। मौनी अमावस्या पर ही प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच विवाद और मारपीट हुई थी। शंकराचार्य के साथ वाराणसी में बैठक कर आगे की रणनीति तय कर ली गई है।

जो कंपनी देगी बिहारवासियों को नौकरी... उन पर मेहरबान रहेगी नीतीश सरकार

पटना (एजेंसी)। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का फोकस अब युवाओं की जॉब और रोजगार पर हो गया है। चुनाव के वक्त अगले पांच साल में राज्य के 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को जॉब और रोजगार देने का जो वादा सुशासन बाबू ने किया था, राज्य सरकार ने अब इसके अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। जल्द ही राज्य के युवाओं के लिए आईटी और सेवा क्षेत्र में रोजगार के बड़े मौके आने वाले हैं।

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत बिहार में कॉल सेंटर या ग्लोबल सेंटर स्थापित करने वाली अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियों को नीतीश सरकार वित्तीय मदद प्रदान करेगी। ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के मौके मिल सके और उन्हें काम की तलाश में दूसरे राज्य न जाना पड़े। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है।

नई नीति के तहत, यदि कोई वैश्विक स्तर की कंपनी बिहार में अपना कॉल सेंटर या क्षमता केंद्र स्थापित करती है, तब उसके कुल पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के रूप में सरकार देगी। यह अनुदान राशि अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक हो सकती है। यदि कंपनी बिहार के मूल निवासियों को अधिक संख्या में रोजगार देती है, तब इस अनुदान की सीमा को और बढ़ाया जा सकेगा। अनुदान का लाभ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनियों को कार्यालय का किराया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अन्य परिचालन खर्चों पर भी सहायता मिलेगी।

खतरे में देहरादून की हरियाली, काटने पड़ सकते हैं 20 हजार पेड़

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के देहरादून जिले के साल के वनों पर हीपलो कीट (साल बोरर कीट) के बढ़ते हमले से हरियाली खतरे में आ गई है। यह कीट साल के पेड़ों को भीतर से खोखला करता है, जिससे उनका जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। हीपलो सबसे पहले पेड़ की छाल में छोटे छेद बनाकर अंडे देता है। अंडों से निकलने वाली लार्वा तने के अंदर सुरंग बनाकर हृदयकाष्ठ को खोखला करती है। इससे पेड़ का पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाता है, और समय के साथ पेड़ ऊपर से सूखकर कमजोर होकर गिरने लगता है। प्रभावित पेड़ों से तने में छेद, रस का रिसाव और बुरादा गिरना दिखाई देता है, जो संक्रमण के प्रमुख संकेत हैं।

उत्तराखंड वन विभाग के अनुसार देहरादून वन प्रभाग में करीब 12 हजार, कालसी में 5000 और मसूरी में 3000 से अधिक साल के पेड़ हीपलो से प्रभावित हैं। तीनों प्रभागों में साल के वनों की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है। गंभीर रूप से संक्रमित पेड़ों को कटान (कंटेनमेंट फेलिंग) के माध्यम से जंगल से बाहर निकालकर नष्ट किया जाता है, ताकि कीट का फैलाव रोका जा सके। कम प्रभावित पेड़ों में कीट आकर्षक ट्रैप, तने पर कीटनाशक पेस्टिंग और जंगल की सफाई जैसे उपाय किए जाते हैं। इतना ही नहीं वन विभाग ने समस्या के समाधान के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) की टीम से मदद मांगी है। एफआरआई ने देहरादून वन प्रभाग का निरीक्षण कर लिया है, जबकि कालसी और मसूरी में टीम का दौरा प्रस्तावित है। वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अरुण प्रताप के अनुसार, हीपलो का ठोस उपचार नहीं है, लेकिन संक्रमित पेड़ों की पहचान और उचित कार्रवाई संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करती है। सालाना कटान के अनुसार हर वर्ष लगभग 2000 पेड़ इस कीट के कारण काटने पड़ते हैं। इस वर्ष हीपलो कीटों का प्रकोप सामान्य से अधिक होने की आशंका है, जिससे देहरादून के साल के वनों को गंभीर नुकसान का खतरा है। वन विभाग लगातार निरीक्षण, कीट नियंत्रण और जंगल की सफाई के माध्यम से इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है।

इन खास ट्रैपों में कीट आकर्षित होकर फंसते हैं। इसके लिए साल के कुछ पेड़ों को काटकर कीटों के लिए चारा तैयार किया जाता है। कई जगह इससे 50 से 70 प्रतिशत तक कीट पकड़ने में सफलता मिलती है। यह कम प्रभावित पेड़ों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा तने पर कीटनाशक का छिड़काव/पेस्टिंग (वैज्ञानिक निर्देश अनुसार) किया जाता है। इसमें लार्वा और वयस्क कीट मर जाते हैं। इसके अलावा जंगल की सफाई और सूखी लकड़ी हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। क्योंकि सूखे पत्ते, टूटे तने, मरी लकड़ी आदि कीट के प्रजनन स्थान बनते हैं। इनकी सफाई संक्रमण को रोकने में बहुत मदद करती है।

हर साल 2000 पेड़ों को पड़ता है काटना

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष हीपलो कीटों का प्रकोप कुछ अधिक है। क्योंकि, सामान्य रूप में साल के पेड़ों में यह कीट पाए ही जाते हैं। जिस कारण एक वन प्रभाग में औसतन दो हजार के करीब पेड़ों को इस कीट रोग के कारण काटना पड़ जाता है। इस वर्ष कुछ अधिक पेड़ इस कीट की भेंट चढ़ सकते हैं।

बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप कहा- वोटर्स की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हो रही हेराफेरी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य प्रशासन और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि अधिकारियों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हेराफेरी करने के गैर-कानूनी आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला एक बेशर्म गठजोड़ करार दिया है। अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कथित व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) की ओर से अधिकारियों को विशेष निर्देश भेजे गए हैं। इस कथित संदेश में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी स्थिति में नॉट वेरिफाइड (सत्यापित नहीं) विकल्प का चयन न करें।

अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने हर दिन 3,000 वेरिफिकेशन का लक्ष्य पूरा करने का दबाव बनाया है, जो प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यह आदेश सीधा और स्पष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया में हेराफेरी करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जानबूझकर नॉट वेरिफाइड मार्क करने से रोका जा रहा है, ताकि उन अयोग्य मतदाताओं और फर्जी प्रविष्टियों को मतदाता सूची से बाहर न किया जा सके, जिन्हें टीएमसी ने अपने वोटबैंक के रूप में सूची में शामिल करवाया है। उनके अनुसार, ममता बनर्जी सरकार भारत के चुनाव आयोग के पारदर्शी मतदाता सूची के आदेशों को धता बताने के लिए जिला प्रशासन का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

सुवेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी इस बात से डरी हुई है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई, तो उनका लंबे समय से चला आ रहा चुनावी धोखाधड़ी का खेल उजागर हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक अधिकारों का यह दुरुपयोग केवल सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने भारत के चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि वह एडीएम और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच शुरू करे जो इन गैर-कानूनी निर्देशों को जारी करने या पालन करने में संलिप्त हैं। सुवेंदु अधिकारी ने मांग की है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

एसआईआर में फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे नाम?

-कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, तत्काल हस्तक्षेप और स्वतंत्र जांच की मांग

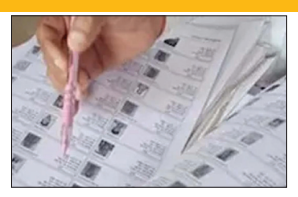

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान फॉर्म-7 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस का दावा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े लोग और अज्ञात व्यक्ति टारगेट वर्गों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि फॉर्म-7 का इस्तेमाल कर लाखों पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस के मुताबिक राजस्थान से शुरू हुई शिकायतें अब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत 12 राज्यों से सामने आई हैं। पार्टी का कहना है कि इससे साफ होता है कि यह मामला न तो स्थानीय है और न ही अलग-थलग है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि जांच में एक समान पैटर्न सामने आया है। इसके तहत केंद्रीकृत प्रणाली के जरिए पहले से छपे हुए फार्म-7 तैयार किए गए, जिनका इस्तेमाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशेष समूहों के खिलाफ सामूहिक आपत्तियां दर्ज कराने में किया गया है।

कांग्रेस ने कहा कि इन फार्म को बाद में बूथ लेवल अधिकारियों को सौंपा गया। कई मामलों में फॉर्म में आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की पहचान, सही मोबाइल नंबर और वैध ईपीआईसी विवरण तक दर्ज नहीं पाए गए जबकि नियमों के तहत यह अनिवार्य है। पार्टी का दावा है कि जिन लोगों के नाम आपत्तिकर्ता के रूप में दर्ज थे, उनमें से कई ने सार्वजनिक रूप से किसी भी फॉर्म को जमा करने से इनकार किया। कुछ मामलों में ये लोग बीजेपी से जुड़े बूथ लेवल एजेंट पाए गए, जबकि कई पूरी तरह अज्ञात व्यक्ति निकले। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि फॉर्म के दुरुपयोग की तत्काल और स्वतंत्र जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई हो और जिन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें तुरंत जोड़ा जाए।

ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर गोवा में सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे नाबालिग

पणजी (एजेंसी)। आधुनिक समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। छोटे बच्चे भी अपना काफी समय इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहे हैं। इस स्थिति के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए गोवा सरकार अब एक कड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार आस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बात का स्पष्ट संकेत खुद राज्य के मंत्री ने दिया है, जिससे देशभर में एक नई बहस छिड़ गई है।

सरकार का प्राथमिक तर्क यह है कि बच्चों को मोबाइल की गंभीर लत, हानिकारक कंटेंट और सोशल मीडिया के कारण पैदा होने वाले मानसिक दबाव से बचाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, यह फैसला अभी शुरुआती चर्चा के चरण में है और पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रस्ताव ने अभिभावकों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के बीच हलचल पैदा कर दी है।

गोवा सरकार के अनुसार, आजकल बच्चे बहुत ही कम उम्र में मोबाइल और सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं। स्क्रीन के सामने घंटों बिताने से न केवल उनकी आंखों और नींद पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि उनके सोचने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर उम्र के लिहाज से अनुपयुक्त वीडियो, गलत जानकारी और अजनबियों से होने वाले संपर्क बच्चों के लिए जोखिम भरे साबित हो रहे हैं। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं भी सरकार के लिए चिंता का एक मुख्य कारण हैं। इन्हीं सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन डिजिटल मंचों से दूर रखने की रूपरेखा तैयार कर रही है।

गौरतलब है कि गोवा सरकार का यह विचार वैश्विक रुझानों से प्रेरित नजर आता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाकर एक मिसाल पेश की है। वहां बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे ऐप्स के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का तर्क है कि ऐसे नियमों से बच्चों का बचपन सुरक्षित रहेगा और वे आभासी दुनिया के बजाय किताबों, खेलों और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकेंगे। गोवा भी इसी मॉडल को अपनाकर बच्चों को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।